संस्करण : भोपाल
वर्ष : 01
अंक : 167
पृष्ठ : 08
मूल्य : 1.00
गुरूवार 17 सितम्बर 2026

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से प्रकाशित

प्रातःकाल एक्सप्रेस

प्रातःकालीन संस्करण

सच से रूबरू

Website:www.pratahkalexpress.in | E-mail :pratahkalexpress@gmail.com | facebook.com/pratahkalexpressnews | https://twitter.com/ratahkalexpress1

सीजेपी प्रदर्शन पर सुप्रीम फैसला

नहीं बदलेगी पुलिस ज्यादती की जांच कर रही कमेटी

एजेंसी

नई दिल्ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित पुलिस ज्यादती की जांच के लिए गठित पांच सदस्यीय हाई पावर कमेटी (एचपीईसी) के पुनर्गठन से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि समिति के सदस्यों के खिलाफ लगाए गए आरोप महज अटकलों और पहले से बनी धारणाओं पर आधारित हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हम समिति के गठन में किसी तरह का बदलाव करने के पक्ष में नहीं हैं, विशेष रूप से तब, जब इसके पुनर्गठन की मांग महज अटकलों और पहले से बनी धारणाओं पर आधारित हो और एचपीईसी के जांच शुरू करने से पहले ही ऐसे विचार व्यक्त किए गए हों।

पैलेट गन से लेकर महिला प्रदर्शनकारियों से दुर्व्यवहार तक की होगी जांच

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एचपीईसी को पैलेट गन के इस्तेमाल, लक्षित हिंसा और महिला प्रदर्शनकारियों के उत्पीड़न से जुड़े मामलों की जांच आगे बढ़ाने को कहा। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों और पुलिस, दोनों पक्षों की ओर से हुई कथित अत्यधिक हिंसा तथा संपत्ति को हुए नुकसान के मुद्दे की भी जांच करने का निर्देश दिया गया।

गोपनीय रखी जाएगी संवेदनशील गवाहों की पहचान

गवाहों के साथ व्यवहार और एचपीईसी के समक्ष अपनी बात रखने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर जताई गई चिंताओं पर पीठ ने कहा कि ऐसे संवेदनशील गवाहों को पर्याप्त सुरक्षा दी जानी चाहिए और उनकी पहचान गोपनीय रखी जानी चाहिए। पीठ ने कहा,'ऐसे संवेदनशील गवाहों की ओर से एचपीईसी

को दिए गए किसी भी बयान या प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के संबंध में पूरी गोपनीयता बनाए रखना आवश्यक होगा।' सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे गवाहों और अन्य संबंधित पक्षों को अपने दस्तावेज और साक्ष्य उपलब्ध कराने की सुविधा देने के लिए एक अलग ऑनलाइन पोर्टल बनाया जा सकता है।

एचपीईसी की ओर से स्वतंत्र मध्यस्थ की भूमिका निभाएंगी मोनिका गुसैन

पीठ ने निर्देश दिया कि वरिष्ठ अधिवक्ता मोनिका गुसैन, अधिवक्ता सी. सोलोमन के साथ, एचपीईसी के प्रतिनिधि के तौर पर अदालत की सहायता करेंगी। साथ ही, वे दोनों पक्षों के बीच स्वतंत्र मध्यस्थ की भूमिका भी निभाएंगे। पीठ ने एचपीईसी से जल्द से जल्द एक सदस्य सचिव नियुक्त करने का भी अनुरोध किया, ताकि समिति को अपने कामकाज के दौरान आवश्यक प्रशासनिक, लॉजिस्टिक और सचिवालय संबंधी सहायता मिल सके।

याचिकाकर्ताओं ने उठाया था हितों के टकराव का सवाल

इससे पहले, समिति के पुनर्गठन की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने दलील दी थी कि समिति के एक सदस्य, जो पूर्वोत्तर राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) रह चुके हैं, के मामले में 'हितों का टकराव' हो सकता है। उनका कहना था कि समिति के उक्त सदस्य एक ऐसे वरिष्ठ पदाधिकारी के करीबी मित्र हैं, जिनकी भूमिका जांच के दायरे में आ सकती है। वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने भी प्रशांत भूषण की दलीलों का समर्थन किया। वहीं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इन दलीलों का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट से ऐसे आरोपों को नजरअंदाज करने का आग्रह किया।

चिटफंड मामले में कोलकाता के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी

एजेंसी

कोलकाता। चिटफंड से जुड़े कथित वित्तीय घोटाले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार सुबह कोलकाता के कई इलाकों में एक साथ तलाशी अभियान चलाया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, शहर में कम से कम छह ठिकानों पर ईडी की टीमें पहुंचीं। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के लिए केंद्रीय सशस्त्र बलों के जवान भी तैनात रहे। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, ईडी की एक टीम सुबह करीब सात बजे उत्तर कोलकाता के नारकेलडांगा इलाके में एक व्यवसायी के आवास पर पहुंची। व्यवसायी का नाम अब्दुर जब्बार मोल्ला बताया गया है। जांच कथित तौर पर चिटफंड के जरिये जुटाई गई रकम और उसके विभिन्न कारोबार में इस्तेमाल से संबंधित है। हालांकि, इन आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। ईडी सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक, जांच का संबंध एपीएम नामक चिटफंड या निवेश नेटवर्क से बताया जा रहा है। एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि निवेशकों से जुटाई गई रकम कहां भेजी गई और क्या उसे दूसरे कारोबार, निर्माण या रियल एस्टेट से जुड़े कामों के माध्यम से निवेश या स्थानांतरित किया गया। नारकेलडांगा के अलावा नेताजीनगर और रविंद्र सरोवर इलाके में भी ईडी की टीमें पहुंचीं। नेताजीनगर में अब्दुर जब्बार मोल्ला से कथित रूप से जुड़े एक व्यक्ति के आवास पर भी तलाशी ली गई। जांचकर्ताओं ने संबंधित लोगों के वित्तीय लेनदेन, दस्तावेज और अन्य रिकॉर्ड की जांच की।

'कारगिल, पीओके और सर क्रीक देने की थी तैयारी': निशिकांत दुबे का कांग्रेस पर आरोप

हवाना बैठक का दिया हवाला

एजेंसी

नई दिल्ली । झारखंड के गोड्डा सीट से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने जुलाई 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के बाद तत्कालीन यूपीए सरकार की पाकिस्तान नीति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने सीमा पार आतंकवाद का जवाब सैन्य कार्रवाई से देने के बजाय अमेरिकी दबाव के बीच कूटनीतिक बातचीत का रास्ता चुना। एक्स पर साझा किए गए अपने पोस्ट में दुबे ने 2006 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद की परिस्थितियों की तुलना 2025 के पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद किए गए 'ऑपरेशन सिंदूर' से की। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से दोनों घटनाओं के बाद अपनाए गए तौर-तरीकों को लेकर जनता के सामने जवाब रखने को कहा।

हवाना बैठक को लेकर निशिकांत दुबे का दावा

निशिकांत दुबे ने 16 सितंबर 2006 को हवाना में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के बीच हुई मुलाकात का हवाला दिया। उन्होंने इस बैठक को अमेरिका के दबाव में हुई कूटनीतिक पहल बताया। दुबे के मुताबिक, यह मुलाकात ऐसे समय हुई थी जब जुलाई 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों से देश में भारी आक्रोश था। इन धमाकों में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई थी, जबकि हजारों लोग घायल हुए थे और कई लोगों को गंभीर

शारीरिक नुकसान पहुंचा था। दुबे का आरोप है कि हमलों के बाद देश में पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही थी, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व ने सैन्य जवाब देने के बजाय बातचीत के जरिए तनाव कम करने का रास्ता चुना।

सोनिया गांधी के नेतृत्व पर भी साधा निशाना

भाजपा सांसद ने अपने बयान में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व पर भी निशाना साधा। उनका दावा है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अगस्त 2006 की बैठक में पाकिस्तान के साथ बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने की दिशा में आगे बढ़ने का फैसला किया गया था। दुबे ने इसे उस समय की सरकार की कमजोर कूटनीतिक नीति के तौर पर पेश किया और आरोप लगाया कि कांग्रेस नेतृत्व अमेरिकी दबाव से प्रभावित था। हालांकि, उनके इस राजनीतिक दावे को उन्होंने अपने पोस्ट में तत्कालीन घटनाक्रम और सामने आए दस्तावेजों के संदर्भ में रखा है।

विकीलीक्स के दस्तावेजों का भी किया जिक्र

निशिकांत दुबे ने अपने आरोपों के समर्थन में विकीलीक्स से सामने आए दस्तावेजों का भी उल्लेख किया। उनका दावा है कि इन दस्तावेजों से संकेत मिलता है कि तत्कालीन यूपीए सरकार व्यापक कूटनीतिक समझौते के तहत कारगिल, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और सर क्रीक जैसे मुद्दों पर रियायत देने की दिशा में आगे बढ़ रही थी। दुबे ने 22 सितंबर 2006 को वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू. बुश और दक्षिण एशियाई नेताओं के बीच हुई बैठकों से जुड़े रिकॉर्ड का भी हवाला दिया। उनके अनुसार, भारत और पाकिस्तान के बीच हुई बातचीत तथा कूटनीतिक पहल की जानकारी अमेरिकी नेतृत्व तक पहुंचाई गई थी।

भारतीय युद्धपोत से भिड़ा पाकिस्तानी जहाज, दिल्ली से लेकर इस्लामाबाद तक हलचल

भारत ने पाक राजनियक को किया तलब

एजेंसी

नई दिल्ली । अरब सागर में अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र के भीतर भारतीय नौसेना के एक जहाज और पाकिस्तानी नौसेना के पोत की टक्कर के बाद भारत ने पाकिस्तान के प्रभारी राजनयिक को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। भारत के मुताबिक घटना में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तानी नौसैनिक पोत का आचरण 1991 के भारत-पाकिस्तान समझौते के अनुच्छेद 10 के विपरीत था। भारत ने इस्लामाबाद में भी पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के समक्ष विरोध दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।

पाकिस्तानी राजनयिक को किया गया तलब

विदेश मंत्रालय ने बताया कि पाकिस्तानी प्रभारी राजनयिक को बुधवार को विदेश मंत्रालय में तलब किया गया। उन्हें पाकिस्तानी अधिकारियों तक भारत की कड़ी आपत्ति पहुंचाने को कहा गया। भारत ने स्पष्ट किया कि समुद्र में सभी सैन्य इकाइयों को पूरी सावधानी बरतनी चाहिए और दोनों देशों के बीच लागू संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करना चाहिए, ताकि इस तरह की घटना दोबारा न हो।विदेश मंत्रालय ने कहा, 'सीडीए को आज विदेश मंत्रालय में तलब किया गया और समुद्र में पाकिस्तानी नौसैनिक इकाइयों के अस्वीकार्य और गैर-पेशेवर आचरण को लेकर उनके समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया गया, जिसके कारण भारतीय नौसेना की एक इकाई से टक्कर हुई।'

अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में हुआ हादसा

विदेश मंत्रालय के अनुसार, यह घटना अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में हुई। हालांकि, टक्कर से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तानी नौसैनिक पोत का आचरण अप्रैल 1991 में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास, युद्धाभ्यास और सैनिकों की आवाजाही के लिए अग्रिम सूचना देने संबंधी समझौते के अनुच्छेद 10 का सीधे तौर पर उल्लंघन था।

इस्लामाबाद में भी दर्ज कराया जाएगा विरोध

भारत ने इस मामले को केवल नई दिल्ली तक सीमित नहीं रखा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस्लामाबाद स्थित भारत के प्रभारी राजनयिक को भी पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के समक्ष इसी तरह का विरोध दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है।

दोनों देशों की सैन्य इकाइयों से सावधानी बरतने की अपील

भारत ने इस घटना के माध्यम से सैन्य गतिविधियों के दौरान सावधानी और संबंधित समझौतों के पालन की आवश्यकता पर जोर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सभी सैन्य इकाइयों को समुद्र में उचित सावधानी बरतने और दोनों देशों के बीच लागू समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करने की जरूरत है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

जिम्बाब्वे के ब्रेंडन टेलर ने सचिन तेंदुलकर का 22 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा

एजेंसी

हरारे। जिम्बाब्वे के अनुभवी विकेटकीपर-बल्लेबाज ब्रेंडन टेलर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले एकदिवसीय मैच में मैदान पर उतरते ही महान भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का लंबे समय से कायम रिकॉर्ड तोड़ दिया। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले जा रहे मुकाबले में टेलर अपना 208वां एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने उतरे। टेलर के एकदिवसीय करियर को अब 22 साल और चार महीने हो चुके हैं।

इसके साथ ही उन्होंने तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 2012 में एकदिवसीय क्रिकेट से संन्यास लिया था और उनका इस प्रारूप में करियर 22 साल और तीन महीने का रहा था। टेलर ने इसी मैदान पर श्रीलंका के खिलाफ 2004 में एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। इस तरह उनके अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत से लेकर अब तक 22 साल से अधिक का समय हो चुका है।

पीएम मोदी आप सेमीकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे

52 देशों की 600 से अधिक कंपनियां लेंगी भाग

एजेंसी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को सुबह लगभग 10 बजे राष्ट्रीय राजधानी स्थित यशोभूमि में सेमीकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। इसमें 52 देशों की 600 से अधिक कंपनियां और प्रतिनिधि भाग लेंगे। यह जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से बुधवार को दी गई। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी में कहा गया कि 17 से 19 सितंबर 2026 तक आयोजित होने वाला तीन दिवसीय सम्मेलन और प्रदर्शनी 'सिलिकॉन से सिस्टम तक: इको सिस्टम का निर्माण' थीम पर आधारित होगा। इसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स

मूल्य श्रृंखला से जुड़े वैश्विक और भारतीय कंपनियां, नीति निर्माता, निवेशक, शोधकर्ता, स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थान और छात्र एकत्रित होंगे। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देना है। समानांतर सत्रों में डिस्प्ले उद्योग में हुई प्रगति, सहयोग और संयुक्त उद्यमों को सुगम बनाने के लिए डिजाइन किए गए छह कंट्री राउंडटेबल, महिला नेतृत्व पर एक मंच आदि शामिल होंगे।

उमर खालिद को 'राष्ट्रवादी' बताने पर सियासी घमासान

भाजपा ने कर्नाटक सरकार से की माफी की मांग

एजेंसी

नई दिल्ली। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष बी. के. हरिप्रसाद द्वारा उमर खालिद को 'राष्ट्रवादी' बताए जाने वाले बयान पर राजनीतिक विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर जोरदार हमला बोला है और माफी की मांग की है। तेलंगाना भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एन. रामचंद्र राव ने कर्नाटक सरकार की कड़ी आलोचना की। हैदराबाद में उन्होंने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, 'यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कर्नाटक सरकार और कर्नाटक के नेताओं ने उमर खालिद को राष्ट्रवादी होने का प्रमाण पत्र दिया है। हम ऐसे लोगों को प्रमाण पत्र दिए जाने की निंदा करते हैं जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं, जो कश्मीर की 'आजादी' और 'भारत के टुकड़े-टुकड़े करने' की बात करते हैं। जब ऐसे लोग देश-विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं, तो एकमात्र राष्ट्रवादी शक्ति जो खुलकर उनका विरोध करती है, वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है।' वहीं, कर्नाटक में भी भाजपा ने इस बयान को लेकर कांग्रेस को घेरा। कर्नाटक

विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलवाडी नारायणस्वामी ने कहा कि कांग्रेस उन लोगों के साथ खड़ी है जो देश को बांटना चाहते हैं। बेंगलुरु में उन्होंने कहा, 'हमें इस बात पर सोचना चाहिए कि कांग्रेस उन लोगों के साथ खड़ी है जो भारत को बांटना और उसके टुकड़े करना चाहते हैं, और बी. के. हरिप्रसाद भी उनके साथ खड़े हैं। इसीलिए वे उसे राष्ट्रवादी कहते हैं। ' झारखंड में भाजपा नेता प्रतुल शाहदेव ने कहा, 'यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि कांग्रेस आतंकवादियों के साथ है। अगर उमर खालिद जैसा व्यक्ति, जिसकी सोच अलगाववादी और आतंकवादी है, उनके लिए राष्ट्रवादी है, तो उन्हें राष्ट्रवाद की परिभाषा ही बदलनी होगी। ' शाहदेव ने उमर खालिद के पुराने मामलों का जिक्र करते हुए कहा, 'उमर खालिद कौन था? वह वही व्यक्ति था जिसका नाम जेएनयू विरोध प्रदर्शन के दौरान सामने आया था, जहां 'भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह' जैसे नारे लगाए गए थे। वह कौन था? वह अफजल गुरु को फांसी दिए जाने का विरोध कर रहा था। अफजल गुरु कौन था? वह वही व्यक्ति था जिसने संसद पर हमला किया था। ' इस बीच, कर्नाटक में एबीवीपी ने भी कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। एबीवीपी के सिटी सेक्रेटरी अभिनंदन मिर्जी ने कहा, 'यह वाकई शर्मनाक है।

कांग्रेस ने यूपीआई को पहले की तरह पूरी तरह से निःशुल्क रखने की मांग की

सरकार अमेरिकी कंपनियों के दबाव में आकर देश के आम नागरिकों, युवाओं और व्यापारियों की जेब पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है।

एजेंसी

नई दिल्ली । कांग्रेस ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के जरिए 2,000 रुपये से अधिक के मर्चेंट भुगतानों पर शुल्क लगाने का रास्ता खोलने के फैसले को लेकर केंद्र सरकार की निंदा की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार अमेरिकी कंपनियों के दबाव में आकर देश के आम नागरिकों, युवाओं और व्यापारियों की जेब पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है। पार्टी ने इस फैसले को तुरंत वापस लेने और यूपीआई को पहले की तरह पूरी तरह से निःशुल्क रखने की मांग की है।

कांग्रेस सोशल मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने बुधवार को यहां पार्टी मुख्यालय में पत्रकार वार्ता में कहा कि सरकार के नए फैसले के तहत 2,000 रुपये से अधिक के हर मर्चेंट यूपीआई भुगतान पर 0.4 प्रतिशत का मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) वसूला जाएगा। सरकार की यह दलील पूरी तरह बेमानी है कि यह शुल्क ग्राहक नहीं बल्कि मर्चेंट चुकाएगा, क्योंकि अंततः व्यापारी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ाकर यह बोझ आम जनता पर ही डालेंगे। श्रीनेत ने दावा किया कि देश में 2,000 रुपये से अधिक मूल्य के 604.8 करोड़ पी2एम (व्यक्ति-से-व्यापारी) यूपीआई लेन-देन होते हैं, जिनका कुल मूल्य 66.22 लाख करोड़ रुपये है। भारत के डिजिटल भुगतान बाजार में फोनपे की 48.9 प्रतिशत और गूगल पे की 37.7 प्रतिशत हिस्सेदारी है। फोनपे में अमेरिका की वॉलमार्ट की 72 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि गूगल पे शत-प्रतिशत अमेरिकी कंपनी गूगल एलएलसी के स्वामित्व वाली है। महंगाई से जूझ रही जनता की जेब काटकर इन विदेशी कंपनियों की कमाई और फोनपे के आगामी आईपीओ के लिए वैल्यूएशन बढ़ाने का काम किया जा रहा है।

उन्होंने सरकार के उस दावे को खारिज किया जिसमें यूपीआई को आर्थिक रूप से बनाए रखने के लिए शुल्क जरूरी बताया गया है। उन्होंने कहा कि पूरे यूपीआई इकोसिस्टम को सुचारु रूप से चलाने के लिए सालाना करीब 20,700 करोड़ रुपये की आवश्यकता होती है।

जयराम रमेश ने विदेश व व्यापार नीति को लेकर मोदी सरकार की निंदा की

नई दिल्ली। कांग्रेस के संचार विभाग के प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने अमेरिकी टैरिफ की धमकी, आव्रजन नियमों में सख्ती और यूपीआई पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लागू करने के फैसले को लेकर बुधवार को केंद्र सरकार की निंदा की। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सीनेट से पारित होने के बाद अब वहां का निचला सदन भारत पर 100 प्रतिशत तक आयात शुल्क लगाने वाले विधेयक पर मतदान करने जा रहा है, जबकि ट्रंप प्रशासन भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) पेशेवरों पर शिकंजा कसते हुए एच-1बी वीजा की लागत बढ़ा रहा है और नौकरी जाने पर तत्काल निर्वासन के कड़े नियम लागू कर रहा है। जयराम रमेश ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर कहा कि अमेरिकी संसद का निचला सदन (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स) एक ऐसे विधेयक पर मतदान करने जा रहा है, जो भारत पर 100 प्रतिशत आयात शुल्क (टैरिफ) लगाने का प्रावधान करता है।

पर्यावरण और जलवायु पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, 17 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल

एजेंसी

नई दिल्ली । राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन जी टी) 19 और 20 सितंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 'पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य' विषय पर दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा।

विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी।एनजीटी ने जारी एक बयान में बताया कि सम्मेलन में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, आवासन एवं शहरी कार्य और विद्युत मंत्री मनोहर लाल, सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना, अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एन जी टी की अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव समेत कई प्रमुख लोग मौजूद रहेंगे।इस सम्मेलन में भारत के अलावा 17 देशों के न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे।

'बिजनेस उत्तरायणी-हिमालयन बिजनेस महाकुंभ 2026' का आयोजन

एजेंसी

नई दिल्ली। 'हिमालयन रिसोर्सेज एन्हांसमेंट सोसाइटी' ने नई दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित विश्व युवक केंद्र में 'बिजनेस उत्तरायणी-हिमालयन बिजनेस महाकुंभ 2026' का आयोजन किया। इस महाकुंभ का मुख्य उद्देश्य हिमालयी क्षेत्र के उद्यमियों, पेशेवरों और स्थानीय हस्तशिल्प को एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करना, व्यापारिक नेटवर्किंग को बढ़ावा देना और 'प्रोफेशनल रिवर्स माइग्रेशन' (अपनी जड़ों की ओर वापसी और विकास) को प्रोत्साहित करना है। यह जानकारी एक विज्ञप्ति में दी गई। विज्ञप्ति के मुताबिक कार्यक्रम की शुरुआत 'हुड़का नाद' की पारंपरिक ध्वनि एवं शकुनाखर के साथ लोकगायक भुवन रावत की द्वारा दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुई। दीप प्रज्ज्वलन महाराष्ट्र एवं गोवा के पूर्व गवर्नर एवं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी के साथ, एयर वाइस मार्शल राजेश भंडारी, उत्तराखंड में महिला उद्यमिता राज्यमंत्री विनोद उनियाल, वरिष्ठ फिल्म निर्देशिका सुशीला रावत, पूर्व कुलपति उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार प्रो. मोहन चंद्र बलोदी, रमेश चंद्र बवाड़ी तथा बिजनेस उत्तरायणी के दिल्ली पदाधिकारियों के साथ किया गया।

कंझावाला मामले में दिल्ली भाजपा करेगी अनुशासनात्मक कार्रवाई, दोनों पक्षों को नोटिस जारी

नई दिल्ली। उत्तर-पश्चिम दिल्ली के कंझावला में भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील कुमार के साथ कथित मारपीट के मामले में दिल्ली प्रदेश भाजपा ने मुंडका के विधायक गजेंद्र दराल और पीड़ित मंडल अध्यक्ष दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कंझावला मंडल अध्यक्ष सुनील कुमार ने मुंडका से भाजपा विधायक गजेंद्र दराल और अन्य पर मीटिंग के बहाने कार्यालय बुलाकर बेरहमी से पीटने का गंभीर आरोप लगाया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि उत्तर पश्चिम संसदीय क्षेत्र में हुई इस घटना के संबंध में प्रदेश नेतृत्व के संज्ञान में जानकारी आई है। प्रदेश नेतृत्व ने मामले को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्रीय सांसद और जिलाध्यक्ष से बातचीत की है। इसके बाद संबंधित विधायक एवं मंडल अध्यक्ष को पत्र जारी कर 16 सितंबर को दोपहर तीन बजे तक दिल्ली भाजपा की अनुशासन समिति के समक्ष अपना स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि मामले को दिल्ली भाजपा की अनुशासन समिति को सौंप दिया गया है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा : नृपेंद्र मिश्रा

अयोध्या। श्री राम मंदिर ट्रस्ट के भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र की बैठकों का दौर भी जारी रहा, उन्होंने राम कथा संग्रहालय में कहा कि राम मंदिर का निर्माण पूरा हो गया है। अंतिम भुगतान की प्रक्रिया चरम पर है और भविष्य में भवन निर्माण की गुणवत्ता बनी रहेगी इसको लेकर कंपनियों से बैंक गारंटी ली जा रही है। 60 से 70 प्रतिशत निर्माण के अंतिम बिलों का इंजिनियर्स इंडिया ऑडिट करेगी। डिजिटलकैलेंडर चुनेंराम कथा संग्रहालय में बनने वाली 20 गैलरियों के निर्माण के लिए 10 अक्टूबर से टेंडर शुरू होंगे। भगवान राम के जीवन चरित्र से जुड़ी गैलरियों का निर्माण होगा। 500 वर्षों से चल रहे राम मंदिर आंदोलन में न्यायालय की भूमिका भी प्रदर्शित होगी। आवश्यक दस्तावेज एकत्र किए जा रहे हैं।

पुष्कर में सामूहिक प्रार्थना के साथ यहूदी नववर्ष रोश हशनाह संपन्न

अजमेर। तीर्थनगरी पुष्कर में यहूदी समुदाय के तीन दिवसीय नववर्ष पर्व रोश हशनाह का सामूहिक प्रार्थना के साथ समापन हुआ। इजराइल से आए करीब 100 पर्यटकों ने धर्मगुरु के सान्निध्य में जयपुर घाट पहुंचकर सूर्यास्त के समय विशेष प्रार्थना की। इस दौरान दुनिया में शांति, भाईचारे और सुख-समृद्धि की कामना की गई। पुष्कर स्थित यहूदियों के धार्मिक स्थल खबाद हाउस से पर्यटक जुलूस के रूप में जयपुर घाट पहुंचे। सूर्यास्त के समय घाट पर सामूहिक प्रार्थना हुई। इसमें सभी लोगों के सुखी और समृद्ध जीवन तथा आपसी प्रेम और भाईचारे की कामना की गई।

खबाद हाउस के प्रबंधक हनुमानप्रसाद बाकोलिया ने बताया कि प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी रोश हशनाह धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के साथ मनाया गया। पर्व के दौरान इजराइल से आए पर्यटकों ने धर्मगुरु सिमशोन गोडस्ट्रीन और उनके परिवार के साथ धार्मिक गतिविधियों में भाग लिया। इस दौरान टोरा ग्रंथ का पाठ, सामूहिक प्रार्थना और अन्य धार्मिक परंपराओं का निर्वहन किया गया।

यूपी के लखीमपुर में 7 मकान नदी में समाए

बिहार में 50 लाख लोग बाढ़ से घिरे, उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

एजेंसी

नई दिल्ली। देश के कई राज्यों में मानसून के सक्रिय रुख के चलते बाढ़ और भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। उत्तर प्रदेश और बिहार में नदियां उफान पर हैं, जिससे लाखों लोग विस्थापित होने को मजबूर हैं। वहीं, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। उत्तर प्रदेश: 26 जिलों में बाढ़, शारदा नदी के कटान से 7 मकान बहे उत्तर प्रदेश में सक्रिय मानसून के चलते 26 जिलों में बाढ़ जैसे गंभीर हालात बने हुए हैं, जिससे करीब 4 लाख की आबादी प्रभावित हुई है:

नदी में समाए घर: लखीमपुर खीरी में शारदा नदी के तेज कटान से पिछले 24 घंटों के भीतर 7 पक्के मकान नदी में समा गए।

मौसम का अलर्ट: मौसम विभाग ने बुधवार को राज्य के 56 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है।

हादसे व अलर्ट: सिद्धार्थनगर में लगातार बारिश के चलते एक दीवार भरभराकर गिर गई। वहीं, सहारनपुर स्थित सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी मंदिर के पास बरसाती नदी में आए उफान के बाद पुलिस व प्रशासन ने श्रद्धालुओं को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने का अलर्ट जारी किया।

बिहार: 15 जिलों में 50 लाख आबादी प्रभावित, नावों में चलने लगे स्कूल

बिहार में बाढ़ का संकट लगातार गंभीर बना हुआ है:

कटिहार में नाव पर कक्षाएं: 15

जिलों की 575 पंचायतों में करीब 50 लाख लोग बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। कटिहार जिले में सरकारी स्कूल और कोचिंग संस्थान जलमग्न हो जाने के कारण शिक्षक नावों में बैठाकर बच्चों को पढ़ाने को मजबूर हैं।

26 जिलों में यलो अलर्ट: राज्य के 26 जिलों में बारिश और आकाशीय बिजली (वज्रपात) गिरने का यलो अलर्ट जारी किया गया है।

राहत कार्य: भोजपुर के ज्वइनिया गांव समेत कई प्रभावित इलाकों में स्थानीय प्रशासन के साथ-साथ समाजसेवी संगठन और जानी-मानी हस्तियां राहत सामग्री बांटने में जुटी हैं।

राजस्थान, गुजरात और पंजाब का हाल

राजस्थान: पाली जिले में बुधवार दोपहर अचानक बदले मौसम के बाद मूसलाधार बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में 17 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रहने का अलर्ट जारी किया है।

गुजरात (ऊना): ऊना क्षेत्र में महज 4 घंटे में 8 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई, जिससे निचले इलाकों के 200 से अधिक मकानों में पानी भर गया।

पंजाब: राज्य के 18 जिलों में अगले कुछ दिनों में मध्यम से तेज बारिश के आसार जताए गए हैं।

केदारनाथ यात्रा: लगातार भूस्खलन और बारिश के खतरे को देखते हुए केदारनाथ पैदल मार्ग पर सुरक्षा मानकों को कड़ा कर यात्रियों को हेलमेट पहनाकर सुरक्षित आगे रवाना किया जा रहा है।

गुजरात में 95 तहसीलों में बारिश

कच्छ की मांडवी में सबसे ज्यादा 6.97 इंच, सौराष्ट्र में भी अलर्ट

एजेंसी

गांधीनगर। गुजरात में एक बार फिर मानसून सक्रिय हुआ है और कई इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी है। खासकर कच्छ जिले में आज सुबह से ही बारिश ने जोरदार दस्तक दी। कच्छ की मांडवी तहसील में सुबह 8 से 10 बजे के बीच महज दो घंटे में 5 इंच से अधिक बारिश होने से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई थी।

राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र, गांधीनगर के आंकड़ों के अनुसार सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक राज्य की 95 तहसीलों में बारिश दर्ज की गई। इनमें कच्छ की मांडवी तहसील में सबसे अधिक 6.97 इंच बारिश हुई। इसके अलावा अबडासा में 2.13 इंच, मुंद्रा में 1.57 इंच, नखत्राणा में 1.30 इंच और भुज में 1.26 इंच बारिश दर्ज की गई। देवभूमि द्वारका की खंभालिया तहसील में 0.87 इंच, ओखा मंडल में 0.79 इंच, सिहोर में 0.71 इंच और नडियाद में 0.63 इंच बारिश हुई।

राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार, मंगलवार सुबह 8 से 10 बजे के दौरान राज्य की 25 तहसीलों में बारिश दर्ज की गई। इस दौरान कच्छ की मांडवी में 5 इंच से अधिक बारिश हुई। मुंद्रा में 0.79 इंच, भुज में 0.59 इंच, नखत्राणा में 0.39 इंच, लखपत में 0.35 इंच, गांधीधाम में 0.24 इंच और अंजार में 0.20 इंच बारिश दर्ज की गई।

सौराष्ट्र के कई इलाकों में भी बारिश

कच्छ के अलावा पोरबंदर, ओखा मंडल, सूरत शहर, कोडिनार, जामनगर, राणावाव, जाफराबाद और

गिर सोमनाथ समेत कई क्षेत्रों में भी बारिश हुई है। भारी बारिश की स्थिति को देखते हुए सौराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव की आशंका बनी हुई है। प्रशासन द्वारा स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

पुष्कर सिंह धामी को जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी समेत कई नेताओं ने दी बधाई

'उत्तराखंड की प्रगति के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं।'

एजेंसी

नई दिल्ली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, गजेंद्र सिंह शेखावत और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, 'उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जन्मदिन की बधाई। वे विभिन्न क्षेत्रों में उत्तराखंड की प्रगति के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। गरीबों को सशक्त बनाने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता भी उतनी ही सराहनीय है। वे दीर्घायु हों और स्वस्थ जीवन जिएं।' लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने एक्स पोस्ट में कहा, 'उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जन्मदिन पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भगवान श्री बद्री-केदार से आपके उत्तम

स्वास्थ्य, दीर्घायु और मंगलमय जीवन की कामना है। ' केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने एक्स पर लिखा, 'उत्तराखंड के ऊर्जावान एवं कर्मठ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, आपको जन्मदिन की आत्मीय बधाई एवं शुभकामनाएं! आपके कुशल नेतृत्व में प्रदेश सर्वांगीण विकास, सुशासन एवं प्रगति के नए आयाम स्थापित करे, यही कामना है। बाबा केदार से आपके उत्तम स्वास्थ्य, सुदीर्घ और यशस्वी जीवन की प्रार्थना करता हूं। 'कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक्स पर लिखा, 'उत्तराखंड के ऊर्जावान एवं कर्मठ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जन्मदिन की आत्मीय बधाई एवं शुभकामनाएं! आपके कुशल नेतृत्व में प्रदेश सर्वांगीण विकास, सुशासन एवं प्रगति के नए आयाम स्थापित करे, यही कामना है। बाबा केदार से आपके उत्तम स्वास्थ्य, सुदीर्घ और यशस्वी जीवन की प्रार्थना करता हूं। 'केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक्स पर लिखा, 'उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं! भगवान आपको सदा स्वस्थ एवं दीर्घायु रखें। '

आईपीएस बुशरा बानो के ट्रांसफर पर छिड़ा सियासी घमासान

छात्रों से अस्सलाम वालेकुम और इंशाअल्लाह कहने पर हुआ था विवाद

एजेंसी

कोलकाता/हैदराबाद। पश्चिम बंगाल कैडर की आईपीएस अधिकारी डॉ. बुशरा बानो के अचानक हुए तबादले ने तूल पकड़ लिया है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बनाए गए एक प्रेरक वीडियो में 'अस्सलाम वालेकुम', 'इंशाअल्लाह' और 'जजाकल्लाह' जैसे शब्दों के इस्तेमाल के बाद उपजे विवाद के बीच राज्य सरकार ने उनका ट्रांसफर कर दिया है। इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। डॉ. बुशरा बानो, जो पश्चिम मेदिनीपुर के खड़गपुर में एडिशनल एसपी (ASP) के पद पर तैनात थीं, उन्हें अब स्टेट आर्म्ड पुलिस (SAP) की चौथी बटालियन में डिप्टी कमांडेंट बनाकर भेजा गया है। उनकी जगह पार्थ घोष को खड़गपुर का नया एडिशनल एसपी नियुक्त किया गया है।

सोशल मीडिया वीडियो से शुरू हुआ विवाद

मामले की शुरुआत 13 सितंबर को पोस्ट किए गए एक वीडियो से हुई, जिसमें आईपीएस बुशरा बानो वर्दी में संघ लोक सेवा आयोग (PSC) के अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन और हौसलाअफजाई कर रही थीं: पारंपरिक शब्दों पर आपत्ति: वीडियो की शुरुआत उन्होंने 'अस्सलाम वालेकुम' से की और बातचीत के दौरान 'इंशाअल्लाह' व अंत में 'जजाकल्लाह' जैसे शब्दों का प्रयोग किया।

संगठन की शिकायत: 'हिंदू लीगल फंड' नामक एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल ने इस वीडियो को साझा करते हुए राज्य के गृह सचिव से शिकायत करने का दावा किया। संगठन ने तर्क दिया कि वर्दीधारी सेवारत अधिकारी को सार्वजनिक संवाद में निष्पक्षता बरतते हुए 'जय हिंद' या 'वंदे मातरम' जैसे राष्ट्रीय उद्घोषनों का प्रयोग करना चाहिए।

भारी ऑनलाइन ट्रोलिंग और विवाद के बाद आईपीएस अधिकारी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से यह वीडियो हटा लिया था।

विपक्ष और सांसदों ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल

आईपीएस अधिकारी के तबादले के बाद कई प्रमुख नेताओं ने खुलकर उनका समर्थन किया और सरकार के रुख की आलोचना की: मोहम्मद अजहरुद्दीन (पूर्व क्रिकेटर व सांसद): अजहरुद्दीन ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'यह बेहद चिंताजनक है कि केवल 'अस्सलाम वालेकुम' और 'इंशाल्लाह' कहने पर एक लोक सेवक को निशाना बनाया जा रहा है।

विजेंद्र गुप्ता 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में हुए शामिल

एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में आयोजित 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन के अंतर्गत वैश्विक सांसदों के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। सम्मेलन की कार्यवाही के तहत गुप्ता 'संसाधन-सीमित संसदों में समावेशिता के उपायों को लागू करना' विषय पर आयोजित संयुक्त नेटवर्क कार्यशाला में प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे।अपने संबोधन के दौरान विधानसभा अध्यक्ष गुप्ता संसाधन-सीमित परिस्थितियों में लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देने, दिव्यांगजनों की भागीदारी तथा संसदों को सभी के लिए अधिक सुलभ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण विचार और अनुभव साझा करेंगे।

योगी कैबिनेट में 23 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर

एक्सप्रेसवे से लेकर शिक्षा और रोजगार तक लिए गए बड़े फैसले

एजेंसी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में विकास और जनकल्याण से जुड़े 23 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। फैसलों में चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे, परिषदीय विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल बनाने, खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने, किसानों को सस्ती दर पर ऋण और पूर्व अग्निवीरों को सरकारी भर्ती में आरक्षण देने जैसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल हैं। बैठक में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, रोजगार, कृषि, स्वास्थ्य और औद्योगिक विकास को लेकर भी निर्णय लिए गए। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेसवार्ता में स्वीकृत प्रस्तावों की जानकारी दी। कैबिनेट में चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को विकसित करने के लिए संशोधित परियोजना प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। 15.172 किलोमीटर लंबे प्रवेश नियंत्रित छह लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण ईपीसी मोड पर कराया जाएगा। परियोजना की अनुमानित लागत 1,008.67 करोड़ रुपये है, जिसका पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। निर्माणकर्ता के चयन के लिए ग्लोबल बिड आमंत्रित की जाएगी। इससे बुंदेलखंड से चित्रकूट धाम तक आवागमन सुगम होने और पर्यटन को गति मिलने की उम्मीद है।

बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रण वाले परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इससे सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और विद्यार्थियों को आधुनिक शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम होगा।

किसानों को छह प्रतिशत ब्याज पर छह लाख तक ऋण

मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत लघु एवं सीमांत किसानों को रियायती ब्याज दर पर दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराने का फैसला किया गया। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के माध्यम से किसानों को छह लाख रुपये तक का ऋण छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर लंबी अवधि के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इससे किसानों को कृषि और ग्रामीण जरूरतों के लिए सस्ती दर पर वित्तीय सहायता मिल सकेगी।

योगी कैबिनेट ने पूर्व अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश जेल वार्डन की सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत पद आरक्षित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके साथ ही पूर्व अग्निवीरों को प्रवर्तन सिपाही (परिवहन) कि सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत पदों पर क्षैतिज एवं आयु सीमा में छूट देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली। इन फैसलों से सैन्य सेवा पूरी कर चुके युवाओं को सरकारी रोजगार के अवसर मिलेंगे।

प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के स्वयंसेवकों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को मुख्यमंत्री पीआरडी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा देने का निर्णय हुआ। इससे पीआरडी जवानों और उनके परिवारों को उपचार के दौरान आर्थिक राहत मिलेगी। कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2025 को मंजूरी दी गई।

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत की विश्व में बढ़ती साख का प्रतीक : मोहन यादव

ब्रिक्स सम्मेलन की अपार सफलता और नई दिल्ली घोषणा पत्र के लिए मप्र के मंत्रिपरिषद् ने प्रधानमंत्री को दी बधाई

एजेंसी

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि नई दिल्ली में हाल ही में हुआ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सच्चे अर्थों में भारत की विश्व भर में बढ़ती भूमिका का प्रतीक बन गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने एक बार फिर दुनिया के सामने अपना वर्चस्व साबित कर दिया है। पहले जी-20 और अब ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता वैश्विक गवर्नेंस में भारत की बढ़ती लीडरशिप का जीवन्त उदाहरण है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मंत्रिगण को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने ब्रिक्स सम्मेलन की सफलता और इस अवसर पर पारित हुए नई दिल्ली घोषणा पत्र को केन्द्र सरकार की कूटनीतिक जीत का प्रमाण बताया। बैठक में ब्रिक्स सम्मेलन की अपार सफलता के लिए पूरी मंत्रिपरिषद द्वारा मेजें थप-थपाकर प्रधानमंत्री मोदी और केन्द्र सरकार को बधाई और शुभकामनाएं देकर अभिनंदन किया गया। मंत्रिमण्डल ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव को उनकी सफल दुबई यात्रा के लिए भी बधाई दी। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में पिछले ढाई वर्षों में दीर्घ अवधि से लंबित रहे बड़े कार्यों के पूरे होने, प्रदेश में परिवहन सेवाओं के विस्तार, ग्रामीण परिवारों को उनके पट्टे के पक्के अधिकार, निवेश के नए अवसरों तथा जनसेवा से जुड़े आगामी अभियानों की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने मंत्रीगण से अपने-अपने प्रभार के जिलों में भी सरकार की सभी योजनाओं और विकास कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नेतृत्व करने का भी आह्वान किया।

नई दिल्ली घोषणा-पत्र

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि ब्रिक्स के 11 सदस्य देश विश्व की लगभग 49.5 प्रतिशत आबादी, 40 प्रतिशत वैश्विक जीडीपी और 26 प्रतिशत वैश्विक व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत की अध्यक्षता के दौरान 25 शहरों में 350 से अधिक बैठकें और कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा ब्रिक्स नई दिल्ली घोषणा-पत्र को सर्वसम्मति से अपनाया गया। शांति, आतंकवाद, व्यापार, वित्त, तकनीक और सतत् विकास पर साझा दृष्टिकोण सामने आया। प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक व्यवस्था को 'पिरामिड ऑफ प्रिविलेज' से 'प्लेटफॉर्म ऑफ पार्टनरशिप' में बदलने और 'रूल टेकर से रूल शेपर' बनने का आह्वान किया।मुख्यमंत्री ने बताया कि आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराई गई और 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम (कश्मीर) में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई। तेज, सुरक्षित एवं कम लागत वाले क्रॉस-बॉर्डर भुगतान तंत्र, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा साइबर सहयोग को समावेशी विकास के महत्वपूर्ण साधन के रूप में बढ़ाने पर जोर दिया गया। मध्य प्रदेश के लिए भी यह सम्मेलन गौरव का विषय रहा। इंदौर में ब्रिक्स युवा उद्यमिता कार्य समूह, कृषि कार्य समूह और 16वीं कृषि मंत्रियों की बैठक हुई।

ब्रिक्स की ऐतिहासिक सफलता से कांग्रेस के 'दिमागी नक्सल' 'नाराज फूफा' बौखलाए : तरुण चुग

एजेंसी

नई दिल्ली। राज्यसभा सांसद एवं भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय प्रभारी तरुण चुग ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रात्रि भोज मेन्यू को लेकर कांग्रेस की टिप्पणियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत की बढ़ती कूटनीतिक शक्ति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैश्विक नेतृत्व की स्वीकार्यता से कांग्रेस के 'दिमागी नक्सल' बौखला गए हैं। उन्होंने कहा कि जिस ब्रिक्स सम्मेलन ने दुनिया के सामने भारत को एक निर्णायक वैश्विक शक्ति और क्षेत्र के ग्लोबल इंजन के रूप में स्थापित किया, कांग्रेस को उसमें भी केवल खाने की थाली दिखाई दे रही है। चुग ने कहा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आतंकवाद के खिलाफ स्पष्ट और मजबूत संदेश, पहलगाम आतंकी हमले की निंदा, सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर सहमति और भारत की शांति, संवाद एवं कूटनीति की नीति को मिला वैश्विक समर्थन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की ऐतिहासिक कूटनीतिक उपलब्धि है। लेकिन कांग्रेस के पास इस सफलता पर बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वह डिनर के मेन्यू पर राजनीति कर रही है। उन्होंने जारी बयान में कहा कि कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि पूरी दुनिया भारत की कूटनीतिक सफलता देख रही है और कांग्रेस शादी में बैठे 'नाराज़ फूफा' की तरह सिर्फ खाने के मेन्यू पर नाराज़गी जता रही है।

चुग ने कहा कि कांग्रेस नेताओं द्वारा भारतीय भोजन और शाकाहारी परंपरा को जाति, क्षेत्र और विचारधारा से जोड़ना उनकी विकृत राजनीतिक मानसिकता को दर्शाता है। भारत की विविधता का सम्मान करने का अर्थ यह नहीं है कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं का अपमान किया जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को यह स्वीकार करना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत आज वह भारत नहीं है जिसकी विदेश नीति कांग्रेस के दौर में वैश्विक शक्तियों के इर्द-गिर्द घूमती थी। आज दुनिया भारत की बात सुनती है और भारत वैश्विक एजेंडा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यूसीसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए तरुण चुग ने कहा कि ओवैसी को यूसीसी में समानता नहीं, अपना वोट बैंक खतरे में दिखाई दे रहा है। उनकी पूरी राजनीति ही मुसलमानों में डर पैदा करने, हर सुधार को मुस्लिम विरोधी बताने और तुष्टिकरण की राजनीति को जिंदा रखने पर आधारित है।

म.प्र. जल निगम के संचालक मंडल की 26वीं बैठक में नाम बदलने के प्रस्ताव को मंत्रि-परिषद को भेजने की दी मंजूरी

म.प्र. जल निगम अब कहलायेगा एमपी वाटर एंड सेनिटेशन कार्पोरेशन : मुख्यमंत्री

प्रातःकाल एक्सप्रेस, भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास (समत्व भवन) में मध्यप्रदेश जल निगम के संचालक मंडल की 26वीं बैठक हुई। बैठक में वर्तमान मप्र जल निगम मर्यादित (एमपीजेएनएम) को पुर्नगठित कर अब मध्यप्रदेश वाटर एंड सेनिटेशन कार्पोरेशन (एमपी-वास्को) बनाने का अहम प्रस्ताव पारित किया गया। संचालक मंडल ने यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव अंतिम अनुमोदन के लिए मंत्रि-परिषद् को भेजने की मंजूरी दे दी। बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश जल निगम अब अपने नए नाम (एमपी-वास्को) और नई जिम्मेदारियों के साथ प्रदेश में जल विकास एवं स्वच्छता प्रबंधन में नए लक्ष्यों और अतिरिक्त संसाधनों के साथ काम करेगा। बैठक में मुख्यमंत्री ने मप्र जल निगम द्वारा विचार एवं अनुमोदन के लिए रखे गये विभिन्न एजेंडा प्रस्तावों को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जल निगम के वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए तैयार संचालक मण्डल के प्रतिवेदन तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनअंकेक्षित वार्षिक लेखाओं का अनुमोदन किया। मुख्यमंत्री ने कैप्टिव मोड के तहत 60 मेगावॉट ग्रिड-कनेक्टेड पवन ऊर्जा परियोजना विकसित करने के लिए गठित परियोजना कंपनी में मप्र जल निगम के प्रतिनिधित्व के लिए प्रबंध संचालक को अधिकृत कर दिया। साथ ही इसी परियोजना के विकास के लिए गठित प्रोजेक्ट कंपनी में डीमैटीरियलाइज्ड रूप में 26 प्रतिशत इक्विटी शेयर रखने का अनुमोदन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने म.प्र. जल निगम के इक्विटी शेयरों के नए पदाधिकारियों को हस्तांतरण तथा जल निगम द्वारा वर्तमान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए तैयार किए गए बजट अनुमान (57 करोड़ रुपए) का अनुमोदन किया। उन्होंने मप्र जल निगम के संचालक मण्डल में स्वतंत्र निदेशक के पद पर श्री सुमित बोस की पुन- नियुक्ति का भी अनुमोदन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन और एक्जीक्यूशन मेथोडोलॉजी के अनुसार मप्र जल निगम के एमडी की टेंडर मंजूरी की तय सीमा 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 25 करोड़ रुपए करने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया। बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपत्तिया उइके, मुख्य सचिव श्री अशोक बर्णवाल, अपर मुख्य सचिव श्री मनीष रस्तोगी, अपर मुख्य सचिव श्रीमती दीपाली रस्तोगी, अपर मुख्य सचिव पीएचई श्री सचिन सिन्हा, प्रमुख सचिव पीएचई श्री मनीष सिंह, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्री संदीप यादव, मप्र जल निगम मर्यादित के एमडी श्री वीएस चौधरी कोलसानी सहित संचालक मण्डल के अन्य सभी सदस्यगण भी उपस्थित थे।

तेंदुए के अवैध शिकार एवं तस्करी के आरोपी की जमानत याचिका ख़ारिज

प्रातःकाल एक्सप्रेस, भोपाल

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एसटीसएफ) मध्यप्रदेश की शिवपुरी क्षेत्रीय इकाई द्वारा वन्यजीव अपराध के गंभीर मामले में गिरफ्तार आरोपी उत्तमनगर पश्चिम, नई दिल्ली निवासी वसीम अकरम की प्रथम नियमित जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायालय, शिवपुरी ने निरस्त कर दी है। आरोपी की ओर से जिला एवं सत्र न्यायालय, शिवपुरी में जमानत याचिका प्रस्तुत की गई। एसटीसएफ की शिवपुरी इकाई एवं अभियोजन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने जमानत का कड़ा विरोध किया। अभियोजन ने तर्क दिया कि आरोपी द्वारा दुष्प्रेरण कर योजनाबद्ध तरीके से वन्यप्राणी अधिनियम की अनुसूची-1 में संरक्षित वन्यजीव तेंदुए का शिकार करवाया गया है। प्रकरण की गंभीरता, अपराध की प्रकृति, आरोपी के विरुद्ध पाए गए डिजिटल साक्ष्यों तथा विवेचना जारी रहने के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जिला एवं सत्र न्यायालय, शिवपुरी ने धारा 483 बीएनएसएस के तहत प्रस्तुत जमानत याचिका निरस्त कर दी। इससे पूर्व भी 31 जुलाई 2026 के प्रकरण में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, शिवपुरी द्वारा अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी की जमानत याचिका निरस्त की गई थी। दोनों प्रकरणों में अब तक कुल 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एसटीएसएफ भोपाल और शिवपुरी इकाई, वन्यप्राणी वनमंडल कूनो और वन मंडल श्योपुर की संयुक्त टीम ने 30 जुलाई 2026 को मुखबिर की सूचना के आधार पर दो आरोपियों की निशानदेही पर वन्यजीव तेंदुए की 42 हड्डियां जब्त की थीं। इस संबंध में वन दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना में सामने आया कि आरोपी वसीम अकरम ने वन्यप्राणी वनमंडल कूनो एवं सामान्य वन मंडल श्योपुर के आसपास के ग्रामीणों को दुष्प्रेरित कर 8 तेंदुओं का शिकार करवाया। आरोपी को 12 अगस्त 2026 को गिरफ्तार किया गया था।

प्रदेश में 26 सितम्बर से 5 अक्टूबर तक आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम

प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में देश की महिलाओं के जीवन में आया बदलाव : मुख्यमंत्री

प्रातःकाल एक्सप्रेस, भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर के अवसर पर प्रदेश में एक माह के सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें 10 दिन आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम के होंगे। प्रदेश में 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक आयोजित आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के कल्याण एवं सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सदैव नारी शक्ति को प्राथमिकता देते हुए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ÷सेवा संकल्प अभियान÷ के अंतर्गत प्रदेश की बहनों से 17 सितम्बर को दीप जलाने का आह्वान करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश सरकार सेवा

के भाव से महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। महिलाओं के जीवन में आया सकारात्मक बदलाव इन्हीं प्रयासों की सफलता का प्रमाण है। महिलाएं सशक्त हुई हैं, आत्मनिर्भर बनी हैं और हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। सेवा और संकल्प की भावना के साथ राज्य सरकार का लक्ष्य है कि मध्यप्रदेश की सभी माता-बहनों को अधिक से अधिक अवसर और सम्मान मिले। हमारी सरकार सशक्त नारी, सशक्त परिवार और समृद्ध मध्यप्रदेश के दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के कार्यकाल में महिलाओं के जीवन में जबरदस्त बदलाव आया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सुशासन के चार स्तंभ- गरीब, किसान, युवा और नारी कल्याण तय किए हैं। उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं में सदैव महिलाओं को सर्वोपरि रखा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी लोकसभा और विधान सभाओं में महिलाओं को आरक्षण सुनिश्चित कराने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में लेकर आए।

अनुदान प्रक्रिया में डिजिटल पारदर्शिता की नई पहल

महिलाओं और बच्चों का सर्वोत्तम हित सर्वोच्च प्राथमिकता : आयुक्त संदीप

प्रातःकाल एक्सप्रेस, भोपाल

महिला एवं बाल विकास विभाग ने मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य से जुड़ी अशासकीय संस्थाओं को दिए जाने वाले अनुदान की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सरल, जवाबदेह और समयबद्ध बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विभाग द्वारा विकसित 'अनुदान पोर्टल' का ऑनलाइन शुभारंभ महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती निर्मला भूरिया ने 15 सितम्बर को किया था। पोर्टल के प्रभावी संचालन के लिए बुधवार को भोपाल के राष्ट्रीय होटल प्रबंधन संस्थान, शाहपुरा में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें करीब 230 प्रतिनिधियों और अधिकारियों ने सहभागिता की। नए डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अशासकीय संस्थाएं अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन से लेकर दस्तावेज अपलोड करने, प्रस्ताव परीक्षण, स्वीकृति, अनुदान वितरण और प्रगति की निगरानी तक की प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी कर सकेंगी। इससे अनुदान प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप कम होने के साथ पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलेगा तथा भुगतान एवं स्वीकृति की प्रक्रिया को अधिक समयबद्ध बनाने में सहायता मिलेगी। आयुक्त महिला एवं बाल विकास श्री संदीप जी.आर. ने कहा कि विभागीय योजनाओं की सफलता का वास्तविक आकलन उनके फील्ड स्तर पर दिखाई देने वाले प्रभाव से होता है। उन्होंने सभी अशासकीय संस्थाओं और विभागीय अधिकारियों से महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण, परामर्श और पुनर्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए संवेदनशीलता और प्रभावशीलता के साथ दायित्वों का निर्वहन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय घटनाओं और उनके बदलते ट्रेंड का चिन्हांकन कर संवेदनशील क्षेत्रों की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन 2047 और राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन समीक्षा बैठक हुई

आंगनवाड़ी, प्राथमिक विद्यालयों में स्क्रीनिंग कैम्प लगाए : राज्यपाल पटेल

प्रातःकाल एक्सप्रेस, भोपाल

राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि सिकल सेल की स्क्रीनिंग में बच्चों की जाँच को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय और आंगनवाड़ी केन्द्रों में कैम्प लगाकर स्क्रीनिंग का कार्य किया जाना चाहिए। राज्यपाल पटेल बुधवार को लोकभवन में राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन 2047 और राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में उपमुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल, उच्च शिक्षा एवं आयुष मंत्री इन्दर सिंह परमार भी मौजूद थे। राज्यपाल ने बैठक उपरांत जनजातीय कार्य विभाग के साथ की धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान एवं पी.एम. जनमन योजना की समीक्षा की। राज्यपाल पटेल ने कहा कि सिकल सेल और क्षय रोग उन्मूलन प्रयासों में जन प्रतिनिधियों का सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से अपेक्षा की है कि सांसद, विधायक से सम्पर्क कर उनके क्षेत्र में सिकल एवं क्षय रोग उन्मूलन अभियान के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था और स्वास्थ्य शिविरों के आयोजन में आवश्यक वित्तीय सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करें। राज्यपाल पटेल ने कहा कि सिकल सेल और क्षय रोग उन्मूलन प्रयासों में जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण घटक है। जरूरी है कि जागरूकता प्रयासों में युवाओं को सहयोगी बनाया जाए। उन्होंने विश्वविद्यालयों,

महाविद्यालयों में छात्रों के बीच जाने और उन्हें सिकल मित्र बनने के लिए प्रेरित करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि क्षय रोग 6 माह में पूरी तरह से ठीक हो सकता है। आवश्यकता रोगी द्वारा नियमित रूप से औषधि का सेवन किया जाए। उन्होंने रोगियों के औषधि सेवन की मॉनिटरिंग की जरूरत भी बताई। राज्यपाल पटेल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रकाशनों का लोकार्पण किया। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने बताया कि प्रदेश में कुल एक करोड़ 34 लाख की सिकल सेल रोग की स्क्रीनिंग हो चुकी है। इनमें से 92 प्रतिशत को जेनेटिक कार्ड का वितरण किया जा चुका है। सिकल मित्र पहल के अंतर्गत 4,825 मित्र बनाएं गए। उनकी संख्या को बढ़ाने के बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश की टी.बी. रोग मुक्त रोगियों की दर 89 प्रतिशत हो गई है। मृत्यु दर में भी कमी आयी है। आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि विभाग द्वारा 30 हजार से अधिक सिकल सेल रोगियों को डोर-टू-डोर जाकर दवा का वितरण किया जा रहा है। सिकल सेल प्रभावित व्यक्तियों से भी सम्पर्क किया जाता है। उन्होंने कहा कि सिकल मित्र बनाने के लिए महाविद्यालयों के छात्रों, राष्ट्रीय सेवा योजना के सदस्यों को प्रेरित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। इसका प्रारंभ सिकल सेल प्रभावित जिलों बड़वानी, धार और अनूपपुर से किया जाएगा। बैठक में जनजातीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष दीपक खांडेकर, राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, आयुष विभाग के प्रमुख सचिव शोभित जैन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव सुखवीर सिंह, राज्यपाल के उप सचिव सुनील दुबे, सचिव जनजाति प्रकोष्ठ मती मीना सिंह सहित प्रकोष्ठ के सदस्य एवं अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे। राज्यपाल पटेल ने जनजातीय कार्य विभाग के साथ की धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान एवं पीएम जनमन योजना की समीक्षा की।

'स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना-2026' की शुरूआत आज से

प्रातःकाल एक्सप्रेस, भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गुरुवार 17 सितंबर को ÷स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना-2026÷ का प्रदेशव्यापी शुभारंभ करेंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम आई.डी.ए. ग्राउंड, गांधी नगर, इंदौर में आयोजित होगा। कार्यक्रम में राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा, राज्यसभा सांसद श्री नितिन नवीन,, विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण और नागरिक उपस्थित रहेंगे।स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी भूमि में अधिकार अभिलेख तैयार किए गए हैं। अब तक 41,568 ग्रामों में कुल 68.47 लाख अधिकार अभिलेखों का निर्माण किया गया है। योजना के तहत लगभग 50 लाख निजी संपत्तियों के अधिकार अभिलेखों का निःशुल्क पंजीयन किया जाएगा। पंजीयन के लिए नागरिकों से स्टाम्प ड्यूटी अथवा पंजीयन शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसकी संपूर्ण राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। योजना के अंतर्गत हितग्राहियों की संपत्ति के आधार पर सुगमता से ऋण उपलब्ध कराने के लिए निर्मित निजी अधिकार अभिलेखों का पंजीयन किया जाएगा। पंजीयन के बाद नागरिक गृह निर्माण, व्यवसाय, कृषि एवं अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण प्राप्त कर सकेंगे। इससे उनकी आजीविका एवं आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। अभियान की सफलता के लिए जनप्रतिनिधियों और नागरिकों को भी इससे जोड़ा जाएगा। प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के लिए ग्राम एवं पंचायत स्तर पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश में पंचायतवार ये शिविर तीन चरणों में आयोजित होंगे। प्रथम चरण 17 से 19 सितंबर, द्वितीय चरण 24 से 26 सितंबर और तृतीय चरण 1 से 3 अक्टूबर तक होगा। शिविर की सूचना संबंधित जिलों द्वारा हितग्राहियों को दी जाएगी। आवेदन के लिए हितग्राही के आबादी भूखंड की लैंड लिंकिंग तथा आवेदक की समग्र आईडी से ई-केवाईसी अनिवार्य होगी।

योजना में लगभग 50 लाख निजी संपत्तियों के अधिकार अभिलेखों का होगा निःशुल्क पंजीयन

शिविरों में संकलित रक्त का व्यवस्थित संधारण एवं सुरक्षित रख-रखाव किया जाये सुनिश्चित

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने शहडोल में सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों की समीक्षा की

प्रातःकाल एक्सप्रेस, भोपाल

उप मुख्यमंत्री एवं शहडोल जिले के प्रभारी मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शहडोल जिले में 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर 2026 तक आयोजित होने वाले सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों एवं विभिन्न गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान के अंतर्गत आयोजित होने वाली सभी गतिविधियों का व्यवस्थित एवं प्रभावी ढंग से संचालन सुनिश्चित किया जाए। सभी कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करने के भी निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के साथ पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने 17 सितम्बर को आयोजित होने वाले रक्तदान

शिविरों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि शिविरों में संकलित रक्त का व्यवस्थित संधारण एवं सुरक्षित रख-रखाव सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने रक्तदान शिविरों के सफल आयोजन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्व से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने जनसेवा संकल्प यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि यात्रा के दौरान निर्धारित सभी आयोजन व्यवस्थित रूप से संपन्न किए जाएं। यात्रा में शामिल दल एवं स्थानीय जनता के बीच प्रभावी संवाद सुनिश्चित किया जाए। यात्रियों के ठहरने एवं भोजन की समुचित व्यवस्था के साथ निर्धारित रूट एवं कार्यक्रम के अनुसार सभी आवश्यक व्यवस्थाएं संबंधित अधिकारी आपसी समन्वय से पूर्ण करें। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत जिले के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में निबंध एवं रंगोली प्रतियोगिताओं का आयोजन प्रतियोगिताओं का व्यवस्थित आयोजन सुनिश्चित किया जाए। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने आंगनवाड़ी केन्द्रों में आयोजित होने वाले 'आंगन का मिलन' कार्यक्रम की भी समीक्षा की।

स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन अभियान की तैयारियों की भी समीक्षा

सेवा से संकल्प अभियान की तैयारियां समय-सीमा में पूर्ण करें, सभी जिलों में गरिमापूर्ण ढंग से आयोजित हों कार्यक्रम : संभागायुक्त शर्मा

प्रातःकाल एक्सप्रेस, भोपाल

संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा ने सभी संभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले 'सेवा से संकल्प अभियान' के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यक्रमों की सूक्ष्म स्तर पर तैयारी सुनिश्चित करें। संबंधित जिलों एवं विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर सभी तैयारियां निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण की जाएं तथा संभाग के प्रत्येक जिले में कार्यक्रम गरिमापूर्ण ढंग से आयोजित हों। संभागायुक्त शर्मा ने बुधवार को कमिश्नर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। बैठक में संयुक्त आयुक्त डॉ. विनोद यादव, उपायुक्त राजस्व मती भारती देवी मिश्रा सहित विभिन्न विभागों के संभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। संभागायुक्त शर्मा ने मध्यप्रदेश में प्रारंभ हुए स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को चिन्हित ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित कर सभी निर्धारित कार्य समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों से कहा कि चयनित ग्रामों में स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन अभियान का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित कर भोपाल संभाग को इस कार्य में प्रदेश का प्रथम संभाग बनाने के लिए सभी अधिकारी समन्वित प्रयास करें। संभागायुक्त शर्मा ने आगामी दिनों में आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के शिविरों की भी सूक्ष्म स्तर पर तैयारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिविर के आयोजन से पहले संबंधित विकासखंड की लंबित सीएम हेल्पलाइन शिकायतों तथा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत समय-सीमा से बाहर के प्रकरणों को चिन्हित किया जाए। इन सभी शिकायतों और प्रकरणों का शिविर में शत-प्रतिशत एवं संतुष्टिपूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि अभियान का मूल उद्देश्य शासकीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और नागरिकों को लोक सेवाओं का समय-सीमा में प्रदाय सुनिश्चित करना है। अभियान के दौरान संवाद, समाधान, संवेदनशीलता और सादगी के साथ अधिक से अधिक जनशिकायतों का संतुष्टिपूर्ण निराकरण किया जाए। संभागायुक्त शर्मा ने सभी संभागीय एवं विभागीय अधिकारियों को जिलों का नियमित भ्रमण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी लंबित सीएम हेल्पलाइन शिकायतों और लोक सेवा गारंटी अधिनियम के समय-सीमा से बाहर के प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करें। विभागीय संस्थाओं का निरीक्षण करने के साथ योजनाओं के क्रियान्वयन की गहन समीक्षा की जाए तथा संबंधित जानकारी मुख्यमंत्री जन अभियान पोर्टल पर दर्ज की जाए।

मेथी दाना किन लोगों को गलती से भी नहीं खाना चाहिए? एक्सपर्ट ने बताया

मेथी दाना पोषक तत्वों से भरपूर होता है. इसको लोग पानी में भिगोकर खाते हैं ताकि वेट लॉस किया जा सके और ब्लड शुगर कंट्रोल में रहे, लेकिन ये हर किसी के लिए सही नहीं है. एक्सपर्ट ने बताया इसे कौन न खाए.

मेथी दाना का सेवन भारतीय रसोई में तड़के के रूप में किया जाता है, लेकिन आज के समय में लोग मेथी दाना का पानी पीने के साथ ही उसे भिगोने के बाद चबाकर भी खाते हैं. इससे वेट लॉस में हेल्प मिलने से लेकर आपकी सेहत को कई फायदे हो सकते हैं. ये फाइबर, आयरन, मैंगनीज, मैग्नीशियम, विटामिन सी जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है. हालांकि मेथी दाना का सेवन सबके लिए सही नहीं रहता है. कुछ लोगों को इससे नुकसान भी हो सकता है.

फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर विपुल ने बताया है कि किन लोगों को मेथी दाना का सेवन सप्लीमेंट की तरह लेने से परहेज करना चाहिए. इसी के साथ इसका सेवन करते वक्त कौन सी सावधानियां बरतना जरूरी होता है. चलिए जान लेते हैं डिटेल के साथ.

प्रेग्नेंसी में न खाएं

एक्सपर्ट विपुल कहते हैं कि प्रेग्नेंसी के दौरान मेथी दाना का सेवन (भिगोकर चबाना या इसका पानी पीना) नहीं करना चाहिए. दाना मेथी यूट्रस यानी गर्भाशय को स्टिम्यूलेट कर सकता है. वहीं ब्रेस्टफीडिंग में भी पहले अपने डॉक्टर से पूछ लें तभी इसका सेवन करें.

सर्जरी होने वाली है तो ध्यान दें

डॉक्टर कहते हैं कि अगर आप मेथी दाना का सेवन कर रहे हैं तो किसी भी सर्जरी से दो हफ्ते पहले इसे बंद कर देना चाहिए. इसी के साथ अपने डॉक्टर को इस बारे में जरूर बताना चाहिए, क्योंकि दाना मेथी ब्लीडिंग को अफेक्ट करता है.

दवाओं के साथ न खाएं

अगर आप वॉर फेरन या फिरएसिट्रोम (ष्द्बह्लह्म्श्द्ब) नाम की ब्लड थिनर दवाएं ले रहे हैं तो भी मेथी दाना का सेवन न करें, क्योंकि मेथी दाना दवाओं के साथ मिलकर ब्लीडिंग को बढ़ा सकता है.

पेट से जुड़ी समस्या में न खाएं

अगर पेट में गैस हो जाए तो लोग मेथी दाना खाने की सलाह देते हैं, लेकिन अगर आपको ढ्ढक्चस् की समस्या है या फिर पाचन बहुत सेंसिटिव है तो मेथी दाना का रेगुलर सेवन करने से बचना चाहिए.

डायबिटीज वाले दें ध्यान

मेथी दाना का सेवन ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में हेल्पफुल माना जाता है, लेकिन अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं या फिर Glimepiride जैसी कोई दवा ले रहे हैं तो मेथी दाना लेने से आपकी शुगर बहुत लो हो सकती है.

थायराइड है तो बरतें सावधानी

डॉक्टर विपुल कहते हैं कि अगर आपको थायराइड है और आप इसकी दवा ले रहे हैं तो मेथी दाना के सेवन और टेबलेट लेने में कम से कम 2 घंटा का अंतर रखें, क्योंकि ये आपकी दवा के ऑबर्जप्शन को स्लो कर सकता है.

नया तेल संकट ज्यादा दूर नहीं

ईरान और सऊदी अरब सचमुच दुश्मन की तरह लड़ रहे हैं और अगर वे शांति की घोषणा के पक्ष में आते हैं तो यह ब्रिक्स की बड़ी सफलता थी। लेकिन दिल्ली की बैठक शुरू होने के पहले ही ईरान और अमेरिका फिर से उलझ कर पश्चिम एशिया के संकट के साथ तेल की कीमतों में नई आग लगा चुके थे। होर्मुज एक बार फिर तेलवाहक जहाजों के लिए संकट का मार्ग बन गया है।यह कहना तो सरासर गलत होगा कि नई दिल्ली में हुए ब्रिक्स सम्मेलन और उसमें जुटे दिग्गजों को दुनिया की खबर न होगी और यमन के हुती विद्रोहियों की जीत का पता न होगा। या फिर खाड़ी में फिर से जंग की स्थिति और सऊदी तेल ठिकानों पर बमबारी से कीमतों में उछाल का पता न होगा। दुनिया की खबर में तो ईरान, रूस और चीन ही नहीं सऊदी अरब भी बड़ा साझीदार हैं और दिल्ली सम्मेलन ने दूसरे देश पर हमला जैसे भारी विवादास्पद मामले में ईरान और सऊदी अरब के बीच एक घोषणापत्र पर सहमति बनाकर दुनिया को चौंकाया भी।ईरान और सऊदी अरब सचमुच दुश्मन की तरह लड़ रहे हैं और अगर वे शांति की घोषणा के पक्ष में आते हैं तो यह ब्रिक्स की बड़ी सफलता थी। लेकिन दिल्ली की बैठक शुरू होने के पहले ही ईरान और अमेरिका फिर से उलझ कर पश्चिम एशिया के संकट के साथ तेल की कीमतों में नई आग लगा चुके थे। होर्मुज एक बार फिर तेलवाहक जहाजों के लिए संकट का मार्ग बन गया है और वहां आ जा रहे जहाजों के साथ ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात समेत खाड़ी के अनेक निशाने बमबारी का ठिकाना बने। इसमें अमेरिका अगुआ रहा जबकि उसके जहाजों को भी निशाना बनाए जाने की खबर आई। और हम लोग अतिथियों के सत्कार और सुरक्षा के लिए शानदार आयोजन में लगे रहे तब तक दुनिया में कच्चे तेल की कीमत करीब बीस फीसदी ऊपर पहुंच गई।अब सरकारी आयोजन से और तैयारियों को हम किस मुंह से गलत बताएंगे लेकिन जिस तरह से हमारी मीडिया भी पश्चिम एशिया के इस विवाद के बढ़ने के साथ तेल की कीमतों वाले सवाल को भूली हुई थी वह हैरान करने वाला है। जबकि यह भी हुआ कि इस संकट की परछाई हमारे शेयर बाजारों और अर्थव्यवस्था के अन्य पक्षों पर पड़ी और उससे स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लग जाता है। हम यह तो बताते रहे कि ब्रिक्स देशों में दुनिया की कितनी आबादी है और दुनिया के जीडीपी में उनका हिस्सा किताना है। हम यह भी बताते रहे कि अमेरिका और यूरोप ही नहीं हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में इस आयोजन और इसकी सफलता को लेकर जितना जलन है। अमेरिकी राष्ट्रपति नए सचमुच में ऐसे बयान दिए भी। उनके इन बयानों और ईरान पर हमले के पीछे उनकी अपनी नीति भी है और एक किस्म की अनिवार्यता भी।लेकिन हुती विद्रोहियों ने इसी बीच जिस आसानी से बाब एल मांदेब द्वीप समेत कई नए द्वीपों और इलाकों पर अपना कब्जा जमा लिया वह दुनिया में तेल की आपूर्ति के रास्ते में नई बाधा बनकर सामने आया। और कोढ़ में खाज की तरह ट्रम्प का यह बयान भी इसी के साथ आ गया कि अमेरिका की हुती विद्रोहियों के साथ बातचीत हुई है और वे अमेरिका द्वारा कार्रवाई न करने की मांग कर रहे हैं। इस मांग पर हमें कोई आपत्ति नहीं है।

पिछली बार तीन साल पहले जब इन विद्रोहियों का इस द्वीप पर कब्जा हुआ था तो लाल सागर से तेल की आपूर्ति आधी रह गई और स्वेज नहर होकर आने वाला परिवहन भी प्रभावित हुआ। इस कब्जे के पहले रोज 93 लाख बैरल तेल वहां से गुजरता था जो घटकर 46 लाख बैरल रह गया। इस बार उनकी जीत ज्यादा बड़े इलाके में हुई है और माना जा रहा है कि वे तेल आपूर्ति वाले जहाजों को ज्यादा परेशान करेंगे, ज्यादा वसूली करेंगे। और अगर अमेरिका उनके खिलाफ कार्रवाई में चूका तो बाकी दुनिया के लिए खतरा बढ़ेगा।ट्रम्प की इस बात पर यकीन करने वाले कम लोग नहीं हैं क्योंकि होर्मुज और तेल के धंधे में नई दिलचस्पी लेने के बावजूद अमेरिका पहली बार सऊदी अरब समेत खादी के अपने मित्र देशों को ईरानी हमले के मामले में अकेला जैसा बना दिया है जबकि इन देशों से उसने सुरक्षा संधि कर रखी है। अभी पिछले नवंबर में ही ट्रम्प और सऊदी सुल्तान मोहम्मद बिन सलमान के बीच रक्षा समझौता हुआ था। असल में ट्रम्प अमेरिका में अपनी कमजोर राजनैतिक स्थिति के मद्देनजर ऐसी सारी गारंटियों को भूल रहे हैं क्योंकि अमेरिकी लोग बाहर सैन्य दखल का नाम सुनते ही और भड़क जाते हैं। दूसरी ओर वे तेल की कमाई से अमेरिकी खजाना भरकर अपनी राजनीति चमकाना भी चाहते हैं। वेनेजुएला का तेल वे अपना मानकर बेच ही रहे हैं और होर्मुज पर नियंत्रण के माध्यम से वे मध्य पूर्व के तेल बाजार से मलाई खाना चाहते हैं। अब उनकी जो भी राजनैतिक और आर्थिक मजबूरियां हों दुनिया उनकी योजना से ही चले यह जरूरी नहीं है। दिल्ली में सऊदी अरब और ईरान का एक घोषणापत्र पर सहमत होना उनको पसंद नहीं आ सकता। इसी तरह मक्का संधि के जरिए सऊदी अरब ने अपनी सुरक्षा का वैकल्पिक रास्ता भी बनाया है।लेकिन अमेरिका अगर हुती विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई से हिचकता है या शांत बैठ जाता है तो दुनिया का तेल संकट और बढ़ेगा और अभी अगर कच्चा तेल 110 डालर प्रति बैरल पहुंचा है तो कल कहां तक जाएगा यह कहना मुश्किल है। अभी ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद छिड़ी जंग के समय होर्मुज से आवाजाही बंद हुई या बहुत कम हो गई थी। उस पूरे ब्यौरे में जाने की जरूरत नहीं है लेकिन तब यह हुआ कि चीन ने तेल का आयात काफी कम कर दिया और तेल के जहाज होर्मुज की जगह लाल सागर से आने जाने लगे। कीमतें बढ़ीं लेकिन वैसी नहीं जितनी इस बार लगा रही हैं।इस बार का खतरा बड़ा होने की वजह सिर्फ हुती जमात की कारस्तानी नहीं है। उससे कच्चे तेल के साथ रिफाइंड तेल अर्थात डीजल और पेट्रोल की आवाजाही भी प्रभावित होगी। भारत जैसे देश नए पिछले संकट के समय चुप्पी सी साधी और रूस से काफी कच्चा तेल लाकर रिफायनिंग करके निर्यात किया और अच्छी कमाई करके अर्थव्यवस्था को अच्छी स्थिति में कर लिया।

इस बार रिफाइन्स तेल की आवाजाही रुकेगी या प्रभावित होगी तो भारत समेत काफी देश तो प्रभावित होंगे ही डीजल -पेट्रोल के ग्राहक पिट जाएंगे।अमेरिका में अभी ही जिस रफ्तार में डीजल की कीमतें साल भर में दो गुना तक हो गईं हैं उससे साफ है कि वहां ज्यादा कोहराम होगा। दूसरे यूक्रेन-रूस लड़ाई में, जिसका ब्रिक्स घोषणापत्र में जिक्र भी नहीं हुआ, रूस की तेल उत्पादन क्षमता प्रभावित हुई है। उनकी रिफायनिंग क्षमता तो नष्ट हुई ही है तेल निकालना भी कम हुआ है। ऐसे में अगर मौजूदा संकट के प्रति ब्रिक समेत दुनिया के सभी सक्रिय राष्ट्र समूह पहल नहीं करेंगे तो तेल का नया वैश्विक संकट आएगा ही।

संपादकीय

भ्रष्टाचार की शपथ!

हमारे समाज में भ्रष्टाचार का वायरस व्यवस्था की रगों में किस कदर घर कर चुका है उसकी बानगी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधियों की हरकत से उजागर हुई। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल होता दिखा, जिसमें पार्षद राउंड टेबल के चारों ओर खड़े होकर शपथ लेते नजर आए कि वे भ्रष्टाचार की कमाई के बंटवारे में ईमानदारी दिखाएंगे। इस घटना के बाद खासा बवाल मचा कि कैसे भ्रष्टाचार की कमाई के लिए भी बाकायदा सिंडिकेट रूप में काम किया जा रहा है। यह वाकया हमारे समाज में व्यवस्था की सड़न को तो दर्शाता ही है, साथ ही भ्रष्टाचारियों के दुस्साहस को भी सामने लाता है। यह घटना हमारी लोकतंत्र की छोटी इकाई में चुने गए नुमाइंदों के चरित्र, सोच और इरादों को तो दर्शाती है, समाज में जीवन मूल्यों के पराभव के बिंब भी उकेरती है। समाज को यह भी संदेश देती है कि हम छोटे-छोटे लालचों के लिये कैसे पार्षद चुनते हैं। जाति, धर्म व क्षेत्र तथा संकुचित आकांक्षाओं के लिये घटिया प्रतिनिधियों को स्थानीय निकायों में अपने हितों पर कुठाराघात के लिये चुनते हैं। यह तो भविष्य बताएगा कि आने वाले समय में इन पार्षदों के खिलाफ पार्टी विशेष की तरफ से क्या कार्रवाई होती है, लेकिन यह घटना भारतीय समाज में घर करते भ्रष्टाचार की एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को जरूर उजागर कर गयी। जब देश आजाद हुआ तो राजस्थान में एक विधायक ऐसा चुना गया, जिसके पास जयपुर जाकर शपथग्रहण में शामिल होने का बस किराया भी नहीं था। बाद में लोगों ने चंदा एकत्र करके उस विधायक को जयपुर भेजा था। आज हमारी जनप्रतिनिधि संस्थाओं में सैकड़ों करोड़पति-अरबपति जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति समाज में आर्थिक विषमता की तसवीर उकेरती है।

गाहे-बगाहे सामने आने वाले आंकड़े बताते हैं कि विधायक व सांसद बनने के बाद उनकी आय दिन दोगुनी-रात चौगुनी गति से बढ़ती है। अगले चुनाव में वे अपनी संपत्ति का जो दिखाई दे सकने वाला ब्योरा जारी करते हैं, उसमें यह समृद्धि स्पष्ट नजर आती है।

निस्संदेह हम जानते हैं कि हमारी व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार समाज को दीमक की तरह खोखला कर रहा है। तमाम अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षणों में भ्रष्टाचार की वैश्विक सूची में हमारी स्थिति शर्मसार करने वाली है। लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर हमारी उदासीनता दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकारों के स्तर पर भी और समाज के भी। बहरहाल, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की नगर परिषद के पार्षदों द्वारा हाथ में जल लेकर ऊपरी कमाई को ईमानदारी से बांटने की खबर परेशान करती है। यह घटना सवाल उठाती है कि नगर निगमों की जो बदहाली है उसके मूल में क्या यह निगम की आय की बंदरबांट ही है? सवाल यह भी है कि जिस दल के ये पार्षद हैं

उसने क्या ऊपरी कमाई के लिए शपथ मामले में कोई कार्रवाई की? प्रश्न यह भी कि जिला प्रशासन ने इस मामले में कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? जैसे कि अक्सर ऐसे मामलों में कार्रवाई करने के बजाय सिर्फ लीपापोती ही होती है, इस मामले में भी ऐसा हुआ है। शीर्ष अधिकारी की दलील थी कि इस संदर्भ में कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है। क्या समाज हित में स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई नहीं की जा सकती? प्रश्न यह भी कि क्या कोई विपक्षी दल का नेता अपने राजनीतिक नफा-नुकसान के लिए मामला दर्ज कराएगा तभी ऐसे मामले में कार्रवाई होगी? बड़ा सवाल इस मामले में समाज की उदासीनता का भी है? यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि समाज में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार ऐसे लोगों के साथ अन्याय होता है जिनका इसमें कोई कसूर नहीं होता। लेकिन उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ती है।

यह भी कि व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ तब आवाज उठाता है जब वह पीड़ित होता है। अन्यथा वह इसे नजरअंदाज कर देता है। बल्कि बहुत सारे लोग इसे सुविधा शुल्क के रूप में स्थापित करने की कुत्सित कोशिश भी करते हैं। जब तक भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रतिरोध के सुर प्रबल नहीं होते हमारे समाज में यह संकट बना रहेगा।

डॉलर की नींव को बिना हिलाए उसे ब्रिक्स की चुनौती

चीन एक व्यापक उद्देश्य पर काम कर रहा है। बीजिंग चाहता है कि युआन की अंतरराष्ट्रीय भूमिका काफी बड़ी हो और उसने अपनी मुद्रा में व्यापार के निपटान के लिए तंत्र का लगातार विस्तार किया है। चीन के व्यापारिक साझेदारों की युआनक्लियरिंग व्यवस्थाओं तक पहुंच बढ़ रही है, जबकि चीन के क्रॉस-बॉर्डर इंटरबैंक भुगतान प्रणाली के विकास ने ऐसा बुनियादी ढांचा तैयार किया है जो स्थापित पश्चिमी वित्तीय नेटवर्क के साथ-साथ काम कर सकता है।डॉलर पर बहस में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि ब्रिक्स अब एक साझा मुद्रा बनाने के राजनीतिक रूप से आकर्षक लेकिन आर्थिक रूप से मुश्किल विचार पर ध्यान नहीं दे रहा है। नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में ज़ोर ज़्यादा व्यावहारिक चीज़ों पर रहा है- सीमा-पार भुगतान को तेज़ और सस्ता बनाना, राष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों को जोड़ना और व्यापार और निवेश के एक बड़े हिस्से का निपटान स्थानीय मुद्राओं में करने की अनुमति देना।

यह अंतर मायने रखता है। डॉलर को दरकिनार करने में सक्षम भुगतान प्रणाली और डॉलर की जगह लेने में सक्षम मुद्रा एक ही चीज़ नहीं हैं। ब्रिक्स पहली चीज़ बनाने के करीब पहुंच सकता है, जबकि दूसरी चीज़ हासिल करने से अभी भी काफी दूर है।वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों ने इंटरऑपरेबिलिटी, स्थानीय-मुद्रा निपटान और तेज़-भुगतान प्लेटफॉर्म और संभावित रूप से केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं के बीच संबंधों को चर्चा के केंद्र में रखा है। भारत का यूपीआई और ब्राज़ील कापिक्स दिखाते हैं कि उभरती अर्थव्यवस्थाएं ऐसी भुगतान प्रणालियां बना सकती हैं जो विकसित अर्थव्यवस्थाओं की प्रणालियों के बराबर या उनसे बेहतर हों। ऐसे नेटवर्क को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने से ब्रिक्स मुद्रा की आवश्यकता के बिना लेनदेन की लागत और कॉरस्पोंडेंट बैंकों पर निर्भरता कम हो सकती है।यह डी-डॉलरलाइज़ेशन का अधिक हासिल करने योग्य रूप है क्योंकि यह दुनिया की मुख्य आरक्षित संपत्ति के रूप में डॉलर की भूमिका को तुरंत बदलने की कोशिश करने के बजाय लेनदेन मध्यस्थ के रूप में डॉलर के उपयोग पर प्रहार करता है।

चीन एक व्यापक उद्देश्य पर काम कर रहा है। बीजिंग चाहता है कि युआन की अंतरराष्ट्रीय भूमिका काफी बड़ी हो और उसने अपनी मुद्रा में व्यापार के निपटान के लिए तंत्र का लगातार विस्तार किया है। चीन के व्यापारिक साझेदारों की युआनक्लियरिंग व्यवस्थाओं तक पहुंच बढ़ रही है, जबकि चीन के क्रॉस-बॉर्डर इंटरबैंक भुगतान प्रणाली के विकास ने ऐसा बुनियादी ढांचा तैयार किया है जो स्थापित पश्चिमी वित्तीय नेटवर्क के साथ-साथ काम कर सकता है।फिर भी, युआन को ऐसी बाधाओं का सामना करना पड़ता है जिन्हें भुगतान तकनीक दूर नहीं कर सकती। चीन पूंजी नियंत्रण बनाए रखता है, मुद्रा डॉलर की तरह स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय नहीं है, और वैश्विक निवेशकों को चीनी वित्तीय बाजारों तक वैसी ही अप्रतिबंधित पहुंच नहीं मिलती है। आरक्षित मुद्रा का दर्जा अंततः सरकारों और निवेशकों की उस मुद्रा में बड़ी मात्रा में संपत्ति रखने की इच्छा पर निर्भर करता है, जिसमें राजनीतिक या वित्तीय तनाव के समय भी शामिल हैं।यहीं पर डॉलर को अपनी जबरदस्त ढांचागत बढ़त हासिल है। अमेरिका दुनिया को बड़ी मात्रा में आसानी से बिकने वाली सरकारी सिक्योरिटीज़, गहरे कैपिटल मार्केट और एक ऐसी करेंसी देता है जिसे बिना ज़्यादा रोक-टोक के सीमाओं के पार ले जाया जा सकता है। यहां तक कि जो देश अमेरिकी प्रभाव को कम करना चाहते हैं, वे भी इस प्रणाली पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं।चीन खुद इस विरोधाभास को दिखाता है, हालांकि स्थिति उतनी तेज़ी से नहीं बदल रही है जितना कभी-कभी माना जाता है। बीजिंग कई सालों से अमेरिकी ट्रेज़रीसिक्योरिटीज़ में अपनी हिस्सेदारी कम कर रहा है। जून 2026 तक, मुख्य भूमि चीन की हिस्सेदारी गिरकर लगभग 633 अरब डॉलर हो गई थी, जो 2008 के बाद का सबसे निचला स्तर है और अपने उच्चतम स्तर से काफी कम है।

यह गिरावट दिखाती है कि चीन सक्रिय रूप से अपने रिज़र्व में विविधता ला रहा है, इसलिए ट्रेज़री में उसके निवेश को अब सिर्फ़ इस बात के सुबूत के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता कि बीजिंग हमेशा के लिए डॉलर प्रणाली से बंधा हुआ है। लेकिन अरबों डॉलर की बची हुई हिस्सेदारी भी मूल समस्या को दिखाती है। अभी भी ऐसा कोई बाज़ार नहीं है जहां चीन कीमतों, मुद्रा या अपने वित्तीय हितों पर असर डाले बिना आसानी से उन रिज़र्व को ले जा सके।

खाड़ी देश एक और महत्वपूर्ण परीक्षा पेश करते हैं। तेल उत्पादक देश डॉलर के बाहर सेटलमेंट व्यवस्थाओं के साथ ज़्यादा सहज हो गए हैं, खासकर इसलिए क्योंकि चीन और भारत के साथ उनके आर्थिक संबंध बढ़ रहे हैं। ब्रिक्स में यूएई की मौजूदगी ऐसी चर्चाओं को और महत्व देती है, जबकि क्षेत्रीय देश एशियाई भागीदारों के साथ पेमेंट लिंक और स्थानीय-मुद्रा व्यवस्थाओं की संभावना तलाश रहे हैं।

लेकिन चुनिंदा लेन-देन के लिए युआन, रुपये या अन्य करेंसी स्वीकार करने की इच्छा का मतलब पेट्रोडॉलर ढांचे को छोड़ना नहीं है। खाड़ी देशों की करेंसी डॉलर से मजबूती से जुड़ी हुई हैं, उनके सॉवरेनवेल्थफंड में बड़ी मात्रा में डॉलर सम्पदा हैं, और अमेरिका उनकी सुरक्षा और निवेश संबंधों के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है। इसलिए, पूरी तरह हटाने के बजाय विविधता लाना ज़्यादा संभव है।

वाशिंगटन करेंसी के मुद्दे को भू-राजनीति से अलग करना भी मुश्किल बना रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने बार-बार ब्रिक्स देशों को कड़ी व्यापारिक आर्थिक दंड की धमकी दी है, अगर वे डॉलर की जगह लेने के लिए बनाई गई किसी मुद्रा का समर्थन करते हैं। उनके प्रशासन ने साथ ही टैरिफ, व्यापार वार्ता और एक्सचेंज-रेट के सवालों का इस्तेमाल आर्थिक नीति के साधनों के तौर पर किया है।अमेरिकी दृष्टिकोण में एक अंतर्निहित तनाव है। वाशिंगटन रिज़र्व-मुद्रा से मिलने वाले असाधारण लाभों को बनाए रखना चाहता है। हालांकि, ट्रंप प्रशासन ने डॉलर को ज़्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने और अमेरिका के बाहरी असंतुलन को कम करने की कोशिश भी की है। रिज़र्व मुद्रा की वजह से दुनिया भर में उसकी लगातार मांग बनी रहती है, जिससे वह घरेलू मैन्युफैक्चरर्स की पसंद से ज़्यादा मज़बूत बनी रह सकती है।आर्थिक ताकत का आक्रामक इस्तेमाल एक और विरोधाभास पैदा करता है। प्रतिबंध, टैरिफ और धमकियां थोड़े समय के लिए अमेरिकी दबदबे को बढ़ा सकती हैं, लेकिन इनसे दूसरे देशों को ऐसी प्रणाली विकसित करने की प्रेरणा भी मिलती है जिनसे वाशिंगटन पर उनकी निर्भरता कम हो सके।

इसीलिए ब्रिक्स भुगतान परियोजना को सिफ़ इसलिए खारिज नहीं किया जाना चाहिए कि कोई दूसरी रिज़र्वमुद्रा अभी दूर की कौड़ी है। इसकी अहमियत धीरे-धीरे होने वाले बदलाव में है। अगर कोई ब्राज़ीलियाई कंपनी किसी भारतीय आपूर्तिकर्ता को सीधे %रियाल% और %रुपये% में भुगतान कर सकती है, या खाड़ी देशों का ऊर्जा व्यापार आपस में जुड़े एशियाई पेमेंट सिस्टम के ज़रिए हो सकता है, तो डॉलर की ज़रूरत वाले ट्रांज़ैक्शन कम हो जाएंगे, भले ही सेंट्रल बैंक उन्हें अपने पास रखना जारी रखें।

इसलिए, उभरती हुई व्यवस्था में डॉलर की जगह कोई दूसरी मुद्रा के लेने के बजाय मौद्रिक बंटवारा होने की ज़्यादा संभावना है। डॉलर अपनी अहमियत खोए बिना मार्केट शेयर खो सकता है। युआन मुख्य रिज़र्व करेंसी बने बिना अपना असर बढ़ा सकता है। स्थानीय मुद्रा आपसी व्यापार में बढ़ सकती हैं, भले ही कोई एक संयुक्त ब्रिक्स मौद्रिक ब्लॉक न बने।नतीजतन, ब्रिक्स ने वह रास्ता चुना है जिसमें तरक्की की सबसे अच्छी संभावना है- डॉलर को खत्म करना नहीं, बल्कि उसे कम ज़रूरी बनाना। अमेरिका की आर्थिक गहराई, संस्थागत अवसंरचनाऔर विशाल प्रतिभूति बाजार के दबदबे को बनाए रखते हैं। उस दबदबे के लिए सबसे बड़ा खतरा शायद किसी बड़ी ब्रिक्स मुद्रा से नहीं, बल्कि हज़ारों ऐसे धन के हस्तांतरणों से हो सकता है जिन्हें धीरे-धीरे यह एहसास हो कि उन्हें अब डॉलर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।

तटीय दीव

में पर्यटकों के लिए है बहुत कुछ

यह स्थान वर्ष 1961 से पहले पुर्तगाली शासन के अधीन था तथा गोवा और दमन के साथ ही इसे स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। ठंडी समुद्री हवा के झोकों तथा प्रदूषण रहित वातावरण के कारण यहां आकर सैलानियों को काफी राहत महसूस होती है।

लंबे विदेशी शासन के कारण दीव के भवनों, किलों, भाषा व संस्कृति तथा जीवनशैली पर पुर्तगाली सभ्यता का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। यहां गुजराती, हिन्दी, अंग्रेजी तथा पुर्तगाली भाषाएं बोली व समझी जाती हैं। यहां के निवासियों को फूलों से बेहद लगाव है इसलिए लगभग हर मकान में फूलों के पौधे आपको अवश्य देखने को मिलेंगे।

दीव का प्रमुख आकर्षण यहां का किला है जोकि लगभग 5.7 हेक्टेयर क्षेत्र में बना हुआ है और सागर के अंदर समाया हुआ प्रतीत होता है। इस किले का निर्माण वर्ष 1535-41 के बीच में गुजरात के सुलतान बहादुरशाह व पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। किले के बीच में पुर्तगाली योद्धा डाम नूनो डी कुन्हा की कांसे की मूर्ति भी बनी हुई है। यहां एक प्रकाश स्तंभ भी बना हुआ है जहां से पूरे दीव का नजारा दिखता है। प्रकाश स्तंभ से आवाज देने पर उसकी प्रतिध्वनि भी सुनाई देती है। पानीकोट का दुर्ग पत्थर की विशाल शिलाओं से बना हुआ है। यह दुर्ग एक समुद्री जहाज के आकार का नजर आता है। इस सुंदर दुर्ग तक पहुंचने के लिए नाव अथवा मोटरबोट की सहायता लेनी पड़ती है क्योंकि यह खाड़ी के मुहाने पर तट से लगभग दो किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दुर्ग के बीचोंबीच एक गिरजाघर व प्रकाश स्तंभ भी है।

आप सेंट पाल चर्च भी देखने जा सकते हैं। वर्ष 1610 में बनी यह चर्च धार्मिक और ऐतिहासिक, दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप दीव घूमने आए ही हैं तो नगोआ बीच जरूर जाएं। इस बीच को भारत के सुंदरतम तटों में से एक माना जाता है। इसका आकार घोड़े की नाल के समान है, जिस पर सुनहरी रेत बिखरी हुई है। इसकी लंबाई दो किलोमीटर है तथा रहने के लिए यहां तंबू लगाने की सुविधा भी है।

सनसेट प्वाइंट सागर तट की गरजती लहरों के बीच एक पहाड़ी पर स्थित है। यहां पर एक उद्यान और ओपन एअर थियेटर बनाया गया है तथा स्नान के बाद कपड़े बदलने के लिए कमरों की भी व्यवस्था है।

दीव के अन्य दर्शनीय स्थलों की बात करें तो केवड़ी में स्थित संगीत फुहारे, सेंट थामस चर्च, नवलखा पार्श्वनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर, जामा मस्जिद, दीव संग्रहालय, गोमती माता सागर तट, घोघला सागर तट व मांडवी नगर आदि प्रमुख हैं। दीव में एक विचित्र आकार का ताड़ का पेड़ होता है जिसमें ऊपर एक के स्थान पर दो तने होते हैं, यह पेड़ अंग्रेजी के वाई आकार का दिखता है, इसको होक्का ताड़ भी कहते हैं।

दीव के हवाई अड्डे पर जेट एअर की मुंबई से प्रतिदिन की उड़ाने हैं। यदि यहां रेल मार्ग से आना चाहें तो आपको निकटतम रेलवे स्टेशन वेरावल पड़ेगा। जहां से आपको दीव तक के लिए बस सेवा उपलब्ध हो जाएगी।

चीन में कीजिए बाघ की सवारी

बीजिंग। बाघ को देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन चीन के एक चिड़ियाघर में पर्यटकों को बाघ की सवारी कराई जा रही है। पर्यटक भी बेखौफ होकर इसका लुत्फ ले रहे हैं। इसका खर्चा मात्र 30 युआन (करीब दो सौ रुपए) है। झेजियांग राज्य के वेनझोऊ चिड़ियाघर में पर्यटकों को बाघ की सवारी करवाई जा रही है।

यही नहीं बाघ पर बैठकर वह अपनी फोटो भी खींचा सकते हैं। हालाँकि कई लोग इसकी आलोचना भी कर रहे हैं। वेनझोऊ मेट्रोपोलिटन न्यूज के अनुसार यहां प्रतिदिन बाघ का शो किया जाता है। करीब बीस मिनट के शो के बाद पर्यटकों को बाघ को छूने के लिए बुलाया जाता है।

चिड़ियाघर के तीन कर्मचारी इस दौरान बाघ पर नियंत्रण रखते हैं। एक कर्मचारी पर्यटक को बाघ पर बैठाकर फोटो खींचता है। इसके एवज में वहाँ मौजूद एक महिला शुल्क वसूलती है। महिला ने बताया यह बाघ पालतू हैं और उसके दाँत और नुकीले नाखून निकाल दिए गए हैं।

वहीं एक पर्यटक लाओ शिबो ने इस पर नाराजगी जाहिर की । उसने कहा यह काफी खतरनाक है। यह जानवरों के साथ दुर्व्यवहार करने जैसा है।

चिड़ियाघर को पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फोटो खिंचाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। चिड़ियाघर के प्रवक्ता ने बताया कि हमने इसके लिए प्रशिक्षित लोगों को रखा है। हम उन्हें इसके लिए भुगतान करते हैं।

घर बैठे घूमें रूस और यूरोप

ट्रांस साइबेरियन रेलवे की विश्व प्रसिद्ध छह दिनी रेल यात्रा का लुत्फ अब अपने कम्प्यूटर पर लिया जा सकता है। यह यात्रा रूस की राजधानी मॉस्को से शुरू होकर व्लादिवोस्तक के प्रशांत महासागर के तट पर समाप्त होती है।

गूगल रशिया और रशियन रेलवे के संयुक्त प्रयासों से एक नई वेबसाइट के जरिए ट्रांस साइबेरियन रेलवे की वर्चुअल जर्नी लॉन्च की गई है।

गूगल पर छह दिन की वीडियो फुटेज लॉन्च की गई है, जो मॉस्को से व्लादिवोस्तक की लगभग छह हजार मील की यात्रा कवर करती है। 6590 रूबल यानि 9836 रुपए प्रति व्यक्ति टिकट वाली यह यात्रा इंटरनेट पर मुफ्त में की जा सकती है।

छह दिनों के इस फुटेज को अगस्त 2009 में तैयार किया गया। इस छह दिन की यात्रा को फिल्माने में कुल 30 दिन लगे। चूंकि इसे केवल दिन की रोशनी में ही रेल की खिड़की से फिल्माया गया है।

यूरोप-एशिया के खूबसूरत नजारे

इस यात्रा के दौरान ट्रांस साइबेरियन रेलवे से दिखने वाल सारे नजारे गुजरते हैं। शीशे सी चमकती खूबसूरत बैकाल झील, वोल्गा नदी, बरगुजीन के पर्वत, तमाम गाँवों के नजारे, बादलों से ढकी पर्वत श्रृंखलाएँ, धुंध में लिपटी वादियाँ और भी ढेरों खूबसूरत नजारे।

लियो तोलस्तोय, रूसी लोकगीत यात्रा में रेल की मधुर ध्वनि का साथ भी चुन सकते हैं और रूसी लोकधुनों का भी आनंद ले सकते हैं। इनसे ऊबे तो लियो तोलस्तोय की क्लासिक रचना 1400 पन्नों की 'वार एण्ड पीस' को भी सुन सकते हैं। साथ ही निकोलाय गोगोल की 'डेड सोल' भी उपलब्ध है। रास्तों को समझने में वर्चुअल गाइड डीजे येलेना भी मदद करेगी।

आँकड़ों में ट्रांस साइबेरियन रेलवे 5753 मील मॉस्को से व्लादिवोस्तक
2 महाद्वीप यूरोप और एशिया
7 टाइम जोन
6 दिन बिना रूके यात्रा
87 रूसी शहर
150 घंटे की वीडियो फुटेज वर्चुअल यात्रियों के लिए

हिन्दी दैनिक प्रातःकाल एक्सप्रेसः- स्वामी, प्रकाशक, फिरदौस फातिमा द्वारा एफ-1, अनमोल होम, प्लाट नं0 53, गोविन्द गार्डेन, राइसेन रोड़, भोपाल मध्य प्रदेश-462023 से प्रकाशित एवं अशोक कुमार खुराना, द्वारा पी.जी. इंफ्रास्ट्रचर एण्ड सर्विस प्रा.लि. करोंद भानपुर बाइपास रोड़ भोपाल मध्य प्रदेश-462037 से मुद्रक। पंजीयन संख्या : **MPHIN/26/A1603,** संपादकः परवेज आलम,मो0 9336781957, पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार। इससे उत्पन्न समस्त विवाद का न्याय क्षेत्र जनपद न्यायालय भोपाल होगा।

अंबानी परिवार की छोटी बहू ने मचाई धूम

राधिका मर्चेंट

का अनोखा Ganpati Look, भरतनाट्यम के हर स्टेप में बदला कांजीवरम ऑउटफिट

मुंबई में अंबानी परिवार का गणेशउत्सव हर साल अपनी भव्यता और खास अंदाज के लिए सुर्खियों में रहता है। इस बार भी 13 सितंबर को एंटीलिया में गणपति का शानदार स्वागत किया गया, जिसमें परिवार के सदस्यों के अलावा बॉलीवुड की कई जानी-मानी हस्तियां भी नजर आईं। इस दौरान राधिका मर्चेंट का अंदाज सबसे अलग और खास रहा। उन्होंने अपने खूबसूरत पारंपरिक लुक से तो सभी का ध्यान खींचा ही, साथ ही भरतनाट्यम की शानदार प्रस्तुति देकर समारोह में भारतीय संस्कृति की खूबसूरत झलक भी पेश की।

राधिका मर्चेंट एक प्रशिक्षित भरतनाट्यम डांसर हैं। गणेश चतुर्थी के मौके पर उन्होंने एंटीलिया में खास डांस परफॉर्मेंस दी। इस प्रस्तुति के लिए उनके ऑउटफिट को भी बेहद सोच-समझकर तैयार किया गया था। इसमें पारंपरिक भारतीय टेक्सटाइल की खूबसूरती के साथ क्लासिकल डांस के लिए जरुरी आराम और मूवमेंट का खास ध्यान रखा गया था। राधिका का यह लुक उनकी डांस परफॉरमेंस के साथ इस तरह मेल खाता नजर आया कि हर स्टेप और मूवमेंट के साथ ऑउटफिट की खूबसूरती और भी निखरकर सामने आई।

पिंक कांजीवरम पहन लगीं बेहद सुन्दर

इस खास मौके के लिए राधिका मर्चेंट ने मशहूर डिज़ाइनर मनीष मल्होत्रा द्वारा तैयार की गई कस्टम ड्रेस को चुना। उनका यह ऑउटफिट हाथ से बने हुए कंजीवरम सिल्क से बनाया गया था। गहरे ज्वेल-पिंक शेड के इस कपड़े पर गोल्ड जरी का खूबसूरत काम किया गया था, जिसने पूरे लुक में रॉयल टच जोड़ दिया।

ऑउटफिट को और खास बनाने के लिए इसमें एंटीक गोल्ड मारोड़ी एंब्रॉयडरी के साथ बारीक जरदोजी वर्क भी किया गया था। आमतौर पर कांजीवरम सिल्क को पारंपरिक छह गज की साड़ी के रूप में देखा जाता है लेकिन राधिका के लिए इसे एक बिलकुल नए अंदाज में पेश किया गया। मनीष मल्होत्रा ने कांजीवरम टेक्सटाइल को प्री-स्टिच्ड स्कर्ट सिल्हूट में तैयार किया, जिससे पारंपरिक फैब्रिक को मॉडर्न ट्विस्ट मिला। खास बात यह रही कि डिज़ाइन सिर्फ खूबसूरती को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया बल्कि भरतनाट्यम के दैरान राधिका के डांस मूवमेंट को आसान बनाने के लिए भी ऑउटफिट को फ्लो को कम्फर्ट दिया गया था।

भरतनाट्यम कर राधिका ने किया बप्पा का स्वागत

राधिका मर्चेंट ने गणेश चतुर्थी के मौके पर भगवान गणेश को एक शानदार डांस के जरिए बप्पा का स्वागत किय। उन्होंने एकदंताय वक्रतुंडाय जैसे भावपूर्ण भक्ति गीत पर अपनी भक्ति ज़ाहिर करते हुए यह उत्सवपूर्ण प्रस्तुति दी। परिवार ने 13 सितंबर की शाम को अपनी मूर्ति, एंटीलिया चा राजा का स्वागत किया। इस दौरान घर को हज़ारों वॉर्म लाइट्स और शानदार फूलों की सजावट से रोशन किया गया था। नीता अंबानी, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट ने स्वागत की रस्मों का नेतृत्व किया। 14 सितंबर को भी जश्न जारी रहा, जब कई बॉलीवुड स्टार्स और जानी-मानी हस्तियां दर्शन के लिए एंटीलिया पहुंचीं। सलमान खान, करीना कपूर खान, सैफ अली खान, कैटरीना कैफ, विक्की कौशल, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, काजोल और सचिन तेंदुलकर अपने परिवार के साथ, और कई अन्य लोग दर्शन के लिए पहुंचे।

दिशा सालियान केस में सूरज पांचोली का आया नाम, एक्टर बोले- 'मैं तो कभी उनसे मिला भी नहीं'

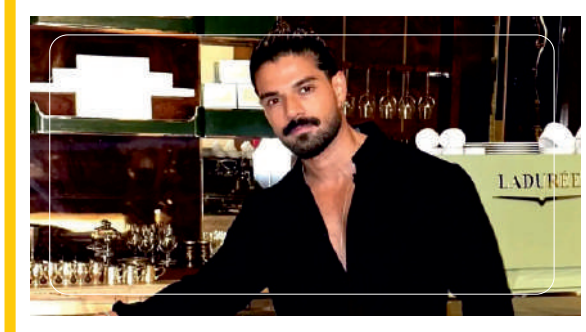

दिवंगत दिशा सालियान की मौत का मामला एक बार फिर चर्चा में है. दिशा सालियान की मौत को लेकर पिछले कुछ सालों में कई तरह के दावे और खबरें सामने आती रही हैं, जिनमें बॉलीवुड के कुछ लोगों के नाम भी जोड़े गए. बॉम्बे हाईकोर्ट ने केस की जांच 6 साल बाद सीबीआई को सौंप दी. जिसका बाद स्न्द्धक्रदर्ज की गई. जांच में कई नामी चेहरों को नाम भी सामने आए हैं, जिसमें एक्टर सूरज पांचोली का नाम भी आया है. इस बीच एक्टर सूरज पांचोली ने इस मामले में अपना नाम आने पर खुलकर सफाई दी है.एक्टर का कहना है कि उनका दिशा सालियान से कभी कोई संपर्क नहीं रहा और वह अपनी जिंदगी में उनसे कभी मिले तक नहीं हैं. ऐसे में इस मामले से उनका नाम जोड़े जाने से वह काफी परेशान हैं. एक्टर ने लंबा-चौड़ा पोस्ट लिखा और अपनी बात रखी है. चलिए जानते हैं सूरज ने क्या कुछ कहा है?

सूरज पांचोली ने किया पोस्ट

सूरज पांचोली ने अपने इंस्टाग्राम पर लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर किया है. इसमें उन्होंने बताया है कि कैसे बिना वजह के उनका नाम सालों से दिशा सालियान केस में घसीटा जा रहा है. एक्टर ने लिखा कि वह काफी समय से इस मुद्दे पर चुप थे, क्योंकि हर खबर या रिपोर्ट पर सफाई देना नहीं चाहते थे. लेकिन जब बार-बार उनका नाम इस विवाद से जोड़ा गया, तो उन्हें सामने आकर कुछ जरूरी बातें साफ करना जरूरी लगा. उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले में जांच एजेंसियां पहले ही उनका बयान दर्ज कर चुकी हैं. अब सूरज ने साफ किया है कि अगर जरूरत पड़ती है तो वह आगे भी किसी भी जांच में पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं.

सूरज ने लिखा कि- पिछले कुछ सालों से दिवंगत दिशा सालियान की दुर्भाग्यपूर्ण मौत से जुड़े विवाद में अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स और बयानों के जरिए मेरा नाम जोड़ा जाता रहा है. जबकि मैं दिशा सालियान से कभी नहीं मिला, न ही मेरा उनसे किसी भी तरह का कोई संपर्क रहा है. यहां तक की मैं कभी आदित्य ठाकरे से भी नहीं मिला हूं.एक्टर ने कहा कि जिस मामले से उनका कोई लेना-देना नहीं है, उसमें बार-बार उनका नाम घसीटा जाना बेहद गलत और परेशान करने वाला है. खासकर तब, जब इस मामले से उनका संबंध साबित करने वाला कोई सबूत या प्रमाण मौजूद नहीं है.

बॉलीवुड में डेब्यू को तैयार सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा के बेटे अबीर सिंह, किस फिल्म का होंगे हिस्सा?

लंबे समय से सलमान खान के बॉडीगार्ड रहे शेरा उर्फ गुरमीत सिंह जॉली को बॉलीवुड सुपरस्टार की परछाई माना जाता है. शेरा हमेशा उनके साथ रहते हैं और भाईजान की देखरेख करते हैं. अब शेरा को उनकी वफादारी का इनाम भी मिल रहा है. शेरा के बेटे अबीर सिंह बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं. पिछले कुछ मौकों पर अबीर सिंह लाइमलाइट में आए हैं और अब एक्टर अपने बॉलीवुड डेब्यू के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. हालांकि इस बात की अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है. लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वे एक ऐसी फिल्म में नजर आएंगे जो पहले से चल रही थी लेकिन बीच में उसका काम रुक गया था.रिपोर्ट्स की मानें तो अबीर सिंह को टार्जन नाम की फिल्म में काम करने का मौका मिला है. इस फिल्म में उनके अपोजिट बॉलीवुड एक्टर आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली भी होंगे. अभी इस फिल्म से जुड़ी ज्यादा डिटेल्स शेयर नहीं की गई हैं लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही इसपर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट सामने आ सकती है.

क्या सतीश कौशिक बना रहे थे फिल्म ?

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो पिछले 3-4 सालों से अबीर सिंह को बॉलीवुड में लॉन्च करने की तैयारी चल रही थी. साल 2022 में ये खबर आई थी कि सलमान खान अपने बॉडीगार्ड शेरा के बेटे अबीर सिंह को इंडस्ट्री में लॉन्च करने जा रहे हैं. फिल्म के निर्देशन के लिए डायरेक्टर और कॉमेडियन सतीश कौशिक का नाम सामने आया था. लेकिन 2023 में सतीश कौशिक के निधन के बाद इस प्रोजेक्ट का काम थम गया था. अब नए सिरे से इस फिल्म पर काम की बात सामने आई है. देखने वाली बात होगी कि अबीर सिंह का बॉलीवुड डेब्यू कैसे होता है और कैसा रहता है.

फैंस कर रहे रिएक्ट

अभी अबीर सिंह की डेब्यू फिल्म को लेकर कन्फर्मेशन आई भी नहीं है लेकिन फैंस के रिएक्शन्स आने शुरू हो गए हैं. लोग उन्हें पहले से ही नई पारी के लिए बेस्ट विशेज दे रहे हैं. वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस खबर से सहमत नजर नहीं आ रहे हैं और ऐसा मान रहे हैं कि सलमान खान के स्टारडम की वजह से अबीर सिंह को मौका मिल रहा है. अबीर सिंह हालांकि बॉलीवुड में इतने भी नए नहीं हैं और वे असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं.

अरिजीत सिंह

की वजह से अटका हुआ है 'किंग' का गाना, शाहरुख खान बोले- मैं सॉन्ग रिलीज करता, लेकिन....

बॉलीवुड के बादशाह कहे जाने वाले शाहरुख खान बस कुछ महीनों के बाद एक बार फिर से बड़े पर्दे पर एक्शन अवतार में नजर आने वाले हैं. वो 'किंग' के नाम से एक एक्शन फिल्म लेकर आ रहे हैं, जो 24 दिसंबर को रिलीज होने वाली है. उनके तमाम फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. 'किंग' के टीजर में स्क्र्य का अंदाज लोगों को काफी पसंद आया था. अब एक फैन ने उनसे फिल्म का एक गाना रिलीज करने की रिक्वेस्ट की. इसपर मजाकिया अंदाज में शाहरुख ने ये कहा कि वो तो गाना रिलीज कर देते, लेकिन अरिजीत सिंह ने अभी तक गाने का काम खत्म नहीं किया है.15 सितंबर को शाहरुख खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ङ्ग (पहले ट्विटर) पर Q&A सेशन किया, जिसे वो स्र्य स्क्र्य सेशन कहते हैं. फैंस ने उनसे कई तरह के सवाल पूछे और उन्हें अलग-अलग अंदाज में फैंस के सवालों के जवाब दिए. एक यूजर ने लिखा, एक गाना रिलीज कर दो सर. #King. इसके जवाब में शाहरुख ने लिखा, गाना रिलीज कर देता, लेकिन अभी अरिजीत दादा को फिनिशिंग टच देना है. वो हर काम में परफेक्शन चाहते हैं, इसलिए उन्हें थोड़ा समय लगता है.

'किंग' में अरिजीत सिंह का गाना

'किंग' का गाना अभी भले ही नहीं आ रहा हो, लेकिन शाहरुख की इस बात से तो तय है कि इस फिल्म में अरिजीत सिंह का गाना सुनने को मिलेगा. गौरतलब है कि अरिजीत ने इसी साल जनवरी में प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास ले लिया था. हालांकि, उन्होंने ये भी कहा था कि पहले से जो प्रोजेक्ट्स उनके पास हैं, वो गाने आने वाले समय में रिलीज होंगे. इससे जाहिर है कि अरिजीत संन्यास से पहले ही 'किंग' का हिस्सा बन गए थे.

3 साल के बाद शाहरुख खान का कमबैक

'किंग' का डायरेक्शन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं. ये फिल्म शाहरुख के तमाम फैंस के लिए इसलिए खास है, क्योंकि इसके जरिए वो तीन साल के बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं. साल 2023 में रिलीज हुई 'डंकी' के बाद उन्हें किसी भी पिक्चर में नहीं देखा गया है. 'किंग' में उनके साथ उनकी बेटी सुहाना खान, अभिषेक बच्चन, रानी मुखर्जी, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर समेत और भी कई बड़े स्टार्स नजर आने वाले हैं.

लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना टीम में वापसी, 6 अक्टूबर को होगा विदाई मुकाबला

एजेंसी

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा के कुछ सप्ताह बाद दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेसी को अक्टूबर में होने वाले मैत्री मुकाबलों के लिए अर्जेंटीना की टीम में शामिल किया गया है। अर्जेंटीना फुटबॉल संघ के अध्यक्ष क्लाउडियो तापिया ने पुष्टि की है कि मेसी को राष्ट्रीय टीम के लिए विदाई मुकाबला खेलने का निमंत्रण दिया गया है। तापिया ने सोशल मीडिया पर कहा, 'हमने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, अपनी टीम के आइकन और कप्तान लियोनेल मेसी को छह अक्टूबर को अर्जेंटीना में अपनी टीम के लिए एक योग्य विदाई के लिए खेलने का निमंत्रण दिया है।' अर्जेंटीना अक्टूबर के अंतरराष्ट्रीय विंडो के दौरान तीन घरेलू मैत्री मुकाबले खेलेगा। मेसी के छह अक्टूबर को ब्यूनस आयर्स में बेनिन के खिलाफ होने वाले मुकाबले में खेलने की उम्मीद है। इससे पहले अर्जेंटीना 30 सितंबर को कॉर्डोबा में बोलीविया और तीन अक्टूबर को ब्यूनस आयर्स में बुर्किना फासो का सामना करेगा मेसी ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की थी। ऐसे में छह अक्टूबर का मुकाबला उनके लिए राष्ट्रीय टीम की जर्सी में विदाई का अवसर बन सकता है।

प्रदेश स्तरीय समन्वय सब जूनियर बालिका कुश्ती प्रतियोगिता के लिए मंडलीय चयन ट्रायल आज

मुरादाबाद। प्रदेश स्तरीय समन्वय सब जूनियर बालिका कुश्ती प्रतियोगिता के लिए मंडलीय चयन ट्रायल 17 सितंबर को नेताजी सुभाष चंद्र बोस सोनकपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम रामगंगा विहार मुरादाबाद में सुबह 11 बजे शुरू होगा। खेल विभाग व उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के समन्त्रय से होने वाली प्रतियोगिता में 10 भार वर्गों में बालिका पहलवानों का चयन किया जाएगा। क्रीड़ाधिकारी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता के लिए 36, 40, 43, 46, 49, 53, 57, 61, 65, 69 और 73 किलोग्राम भार वर्ग निर्धारित किए गए हैं। मंडलीय ट्रायल में चयनित खिलाड़ी 25 से 27 सितंबर तक सुल्तानपुर में आयोजित होने वाली प्रदेश स्तरीय समन्वय सब जूनियर बालिका कुश्ती प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। क्रीड़ाधिकारी सुनील कुमार सिंह ने आगे बताया कि प्रतियोगिता में वर्ष 2009 और 2010 में जन्मी 16 से 17 वर्ष को खिलाड़ी पात्र होंगी। वर्ष 2011 में जन्मी 15 वर्ष की खिलाड़ी चिकित्सक अथवा माता-पिता की अनुमति के प्रमाणपत्र के साथ प्रतिभाग कर सकेगी। खिलाड़ियों की आयु व निवास का सत्यापन जन्म प्रमाणपत्र, आधार कार्ड या पासपोर्ट से किया जाएगा। ट्रावल में शामिल होने वाली खिलाड़ियों को आधार कार्ड साथ लाना अनिवार्य है।

कॉमनवेल्थ क्यू स्पोर्ट्स चैंपियनशिपः अहमदाबाद में इतिहास रचने उतरेगी 18 सदस्यीय भारतीय टीम

अहमदाबाद। भारत की शीर्ष क्यू स्पोर्ट्स प्रतिभाएं अक्टूबर में अहमदाबाद में इतिहास रचने के इरादे से उतरेंगी। कॉमनवेल्थ क्यू स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के दूसरे संस्करण के लिए 18 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। पहली बार इस प्रतिष्ठित बहु-विधा प्रतियोगिता का आयोजन भारत में होगा। चैंपियनशिप का आयोजन 7 से 10 अक्टूबर तक अहमदाबाद के वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया जाएगा। इसमें राष्ट्रमंडल के करीब 46 देशों के खिलाड़ी इंग्लिश बिलियर्ड्स, स्नूकर, 10-बॉल पूल, हेयबॉल और ब्लैकबॉल में हिस्सा लेंगे। एपेक्स स्पोर्ट्स प्रमोशन द्वारा आयोजित और बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन ऑफ इंडिया की मेजबानी में होने वाली इस चैंपियनशिप को वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन ऑफ बिलियर्ड्स स्पोर्ट्स और कॉमनवेल्थ स्पोर्ट की मान्यता प्राप्त है। यह आयोजन भारतीय क्यू स्पोर्ट्स के लिए महत्वपूर्ण अवसर होने के साथ बीएसएफआई के शताब्दी समारोह का भी प्रमुख हिस्सा है।

बाबर आजम की घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट में वापसी, प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी में खेलेंगे

लाहौर। पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान बाबर आजम घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट में वापसी करने के लिए तैयार हैं। बाबर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जारी प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी ग्रेड-1 टूर्नामेंट के लिए उन्हें किसी टीम की टीम में शामिल करने का अनुरोध किया था।

रिपोर्टों के मुताबिक, बाबर ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड की ओर से खेलते नजर आएंगे। इसके साथ ही वह करीब सात साल बाद घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट में वापसी करेंगे। उन्होंने आखिरी बार 2019 में सेंट्रल पंजाब के लिए घरेलू प्रथम श्रेणी मैच खेला था। लाल गेंद के क्रिकेट में बाबर पिछले कुछ समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट शतक 2022 में कराची में न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाया था। वर्ष 2023 के बाद से टेस्ट क्रिकेट में उनका औसत 30.43 रहा है।

एशियाई खेलः मां से किया वादा निभाकर असीमा ने बनाया भारतीय टीम में स्थान

एजेंसी

नई दिल्ली। असीमा अहलावत के लिए शूटिंग का सफर पढ़ाई से शुरू होकर एशियाई खेलों तक पहुंचा है। 18 साल की उम्र में पिस्टल से निशानेबाजी शुरू करने वाली 22 वर्षीय असीमा ने बाद में शॉटगन को अपना खेल चुना। यह बदलाव उन्होंने अपनी मां से किए एक वादे के बाद किया था। मां ने उन्हें शूटिंग में करियर बनाने की अनुमति देने से पहले पढ़ाई में अच्छे अंक लाने की शर्त रखी थी। असीमा ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 98.6 प्रतिशत अंक हासिल कर अपना वादा पूरा किया। अब चार साल बाद रोहतक, हरियाणा की असीमा आइची-नागोया एशियाई खेलों में पदार्पण करने के लिए तैयार हैं। असीमा के खेल से जुड़ने की कहानी भी दिलचस्प है। निर्माण कारोबार से जुड़े परिवार में पली-बढ़ी असीमा ने 2018 राष्ट्रमंडल

खेलों को देखने के बाद निशानेबाजी की ओर आकर्षित होना शुरू किया। उन्होंने एक बयान में कहा, 'मंच पर मनु भाकर और हीना सिद्धू को देखकर मुझे याद है कि मैंने सोचा था, मैं भी किसी दिन ऐसा महसूस करना चाहती हूं।'

असीमा के इस सफर में उनकी मां की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने कहा, 'मेरी मां ने मुझे सिर्फ अनुमति नहीं दी, बल्कि इसके लिए बहुत कुछ छोड़ा भी। वह रोहतक से दिल्ली आ गईं, उन्होंने हमारे पारिवारिक कारोबार को भी स्थानांतरित किया, ताकि मैं ठीक से प्रशिक्षण ले सकूं। मैं इस बात को हल्के में नहीं लेती।' शूटिंग के शुरुआती वर्षों में भी असीमा को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनकी पहली शॉटगन और गोला-बारूद की व्यवस्था होने में करीब आठ महीने लग गए। उन्होंने कहा, 'पदक ही यह बताने का एकमात्र तरीका नहीं है कि आपने कितनी दूर तक सफर तय किया है।' उन्होंने आगे कहा, 'अगर कुछ सही नहीं होता है तो मैं गलती तलाशती हूं, उसे सुधारती हूं और पहले से ज्यादा मजबूती के साथ वापसी करती हूं।' यही सोच 2024 में पेरू में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में भी उनके काम आई। अपने जूनियर करियर के अंतिम वर्ष में एक गलत गणना के कारण वह अंतिम निशाने से चूक गईं और चौथे स्थान पर रहीं। इसके कुछ सप्ताह बाद उन्होंने दिल्ली में आयोजित विश्व विश्वविद्यालय चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। असीमा अपनी प्रगति का श्रेय राष्ट्रीय राइफल संघ को भी देती हैं। उन्होंने कहा, 'राष्ट्रीय राइफल संघ ने मेरे जैसे निशानेबाजों के लिए चीजों को काफी आसान बनाया है।

यूपी स्टेट मास्टर्स बैडमिंटन में बनारस का दबदबा, खिलाड़ियों ने जीते 9 पदक, 65+ आयु वर्ग में आरएन सरकार ने लगाया गोल्डन हैट्रिक, जीता तीन स्वर्ण

एजेंसी

वाराणसी। गाजियाबाद में आयोजित योनेक्स सनराइज उत्तर प्रदेश स्टेट मास्टर्स रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता में वाराणसी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। 12 से 14 सितंबर तक चली प्रतियोगिता में बनारस के मास्टर्स खिलाड़ियों ने अलग-अलग आयु वर्ग में चार स्वर्ण, तीन रजत और दो कांस्य समेत कुल नौ पदक अपने नाम किए।

प्रतियोगिता में वाराणसी के आरएन सरकार (बाला) का प्रदर्शन सबसे खास रहा। उन्होंने 65+ आयु वर्ग में पुरुष एकल, पुरुष युगल और मिश्रित युगल तीनों स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतकर तिहरा खिताब अपने नाम किया।

नीलम सिंह ने भी जीते दो पदकः 50+ आयु वर्ग के महिला एकल में वाराणसी की नीलम सिंह ने रजत पदक हासिल किया। महिला युगल में नीलम सिंह ने

लखनऊ की कल्पना सिंह के साथ जोड़ी बनाकर स्वर्ण पदक जीता। इस तरह नीलम ने प्रतियोगिता में एक स्वर्ण और एक रजत पदक अपने नाम किया। 55+ आयु वर्ग के पुरुष एकल में वाराणसी के डॉ. राजीव कुमार सिंह ने कांस्य पदक हासिल किया।

एशियाई खेलः स्वर्ण पदक बरकरार रखने के इरादे से मैदान में उतरेगी भारतीय महिला कबड्डी टीम

एशियाई खेलों में एक और स्वर्ण पदक जीतना भारतीय महिला खिलाड़ियों के लिए अगली पीढ़ी को प्रेरित करने का अवसर भी होगा।

एजेंसी

नई दिल्ली। एशियाई खेल-2026 में भारतीय महिला कबड्डी टीम अपने स्वर्ण पदक का बचाव करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। कप्तान पुष्पा राणा और अर्जुन पुरस्कार विजेता पूजा काजला ने टीम की तैयारियों पर भरोसा जताते हुए कहा कि भारतीय टीम का लक्ष्य शीर्ष स्थान हासिल करना है।

भारतीय 12 सदस्यीय टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी संभाल रहीं पुष्पा राणा ने कहा कि टीम ने विरोधी टीमों का विश्लेषण करने के साथ अपनी कमजोरियों पर भी काम किया है। उन्होंने एक आधिकारिक बयान में कहा, 'हम परिस्थितियों के अनुसार अभ्यास करते हैं। आगामी मुकाबलों के वीडियो का भी विश्लेषण करते हैं। हमारे कोच हमें पिछली गलतियों और उन क्षेत्रों के बारे में बताते हैं, जिनमें सुधार की जरूरत है। अब हम उन्हीं पहलुओं पर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारी टीम पूरी तरह तैयार है।' एशियाई खेलों में कबड्डी में भारत का दबदबा रहा है और देश ने इस खेल में अब तक

11 स्वर्ण पदक जीते हैं, जिनमें महिला वर्ग के तीन स्वर्ण शामिल हैं। भारतीय महिला टीम ने हांगझोउ एशियाई खेलों में चीनी ताइपे को फाइनल में 26-25 से हराकर स्वर्ण पदक जीता था। पिछले साल नवंबर में भारतीय महिला टीम ने विश्व कप का खिताब भी अपने नाम किया था। राणा ने कहा कि लगातार खिताब जीतने की उम्मीद उनके लिए दबाव नहीं, बल्कि प्रेरणा है। उन्होंने कहा, 'जब हमारी सीनियर खिलाड़ियों ने पहले ही अच्छा प्रदर्शन किया है और अपना इतिहास बनाया है, तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस लय को बनाए रखें। हम इसे दबाव के रूप में नहीं, बल्कि प्रेरणा के रूप में देखते हैं और इस लय को बरकरार रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं।' पुष्पा राणा पहली बार भारतीय टीम की कप्तानी कर रही हैं। हालांकि वह पहले उपकप्तान की भूमिका निभा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि टीम में मौजूद अनुभवी खिलाड़ियों से उन्हें काफी मदद मिल रही है। राणा ने कहा, 'मैं सीनियर खिलाड़ियों पर काफी भरोसा करती हूं, क्योंकि ऋतु नेगी और सोनाली शिंगाटे जैसी खिलाड़ी पहले कप्तानी कर चुकी हैं, इसलिए उनकी सलाह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।'

राणा ने चीनी ताइपे के एशियाई खेलों में भारत के लिए प्रमुख चुनौती पेश करने वाली टीमों में शामिल बताया। उन्होंने पिछले एशियाई खेलों के बेहद करीबी फाइनल का भी जिक्र किया, जिसमें भारत ने चीनी ताइपे को 26-25 से हराया था।

जेम्स रोड्रिगेज ने कोलंबिया की राष्ट्रीय टीम से संन्यास लिया

पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैंने यह हासिल किया।'

एजेंसी

बोगोटा। कोलंबिया के स्टार मिडफील्डर जेम्स रोड्रिगेज ने 15 साल के अंतरराष्ट्रीय करियर के बाद राष्ट्रीय टीम से संन्यास की घोषणा कर दी। 35 वर्षीय रोड्रिगेज ने उत्तरी अमेरिका में हुए हालिया फीफा विश्व कप के बाद अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल को अलविदा कहने का फैसला किया। रोड्रिगेज ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा, 'कई वर्षों, मैचों, खुशी के पलों और मुश्किल दौर से गुजरने के बाद मुझे लगता है कि अब अपनी जिंदगी के एक अध्याय को बंद करने का समय आ गया है– कोलंबिया की राष्ट्रीय टीम के साथ मेरा सफर। इस जर्सी को पहनना एक सपना था, लेकिन यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी थी। 'रोड्रिगेज ने 2011 में ला पाज में बोलीविया के खिलाफ जीत के

दौरान कोलंबिया के लिए पदार्पण किया था। हालांकि 2014 फीफा विश्व कप में उनके शानदार प्रदर्शन ने उन्हें वैश्विक पहचान दिलाई। उन्होंने टूर्नामेंट में गोल्डन बूट जीता और इसके बाद स्पेन के दिग्गज क्लब रियल मैड्रिड से जुड़ गए। रियल मैड्रिड के साथ उन्होंने दो ला लीगा खिताब जीते। इसके अलावा वह बायर्न म्यूनिख और एवर्टन के लिए भी खेल चुके हैं। उन्होंने कहा, 'मैं उन पलों को जीने के लिए भाग्यशाली रहा, जिनकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी–विश्व कप, गोल और अविस्मरणीय रातें; ऐसी जीत जिन्होंने हमें विश्वास करना सिखाया और ऐसी हार जिन्होंने हमें मजबूत बनाया।'

रोड्रिगेज ने कहा, 'जब मैंने राष्ट्रीय टीम के साथ सफर शुरू किया था, तब मेरी इच्छा थी कि जब मैं आगे बढ़ूं तो टीम की जर्सी को पहले से अधिक मजबूत स्थिति में छोड़कर जाऊं। पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैंने यह हासिल किया।'

एशियाई खेल 2026: जापान पहुंची भारतीय महिला क्रिकेट टीम

कोच मजूमदार ने चुनौती को लेकर जताई उत्सुकता

एजेंसी

टोक्यो। हाल ही में टी20 एशिया कप का खिताब जीतने के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम एशियाई खेल 2026 में अपने अभियान के लिए जापान पहुंच गई है। गत चैंपियन भारतीय टीम की नजरें हांगझोउ में 2023 में जीते स्वर्ण पदक का बचाव करने पर हैं। मुख्य कोच अमोल मजूमदार ने कहा कि टीम बहु-खेल आयोजन के माहौल का अनुभव लेने के लिए उत्साहित है।जापान पहुंचने के बाद मजूमदार ने कहा, 'टीम एशियाई खेलों को लेकर उत्साहित है और बहु-खेल आयोजन के माहौल का आनंद लेने के लिए तैयार है। मजूमदार अपने सहयोगी स्टाफ के कुछ सदस्यों के साथ सुबह की उड़ान से जापान पहुंचे। क्रांति गौड़ और श्री चरणी सहित टीम की कुछ खिलाड़ी कोचिंग स्टाफ के साथ जापान पहुंचीं, जबकि टीम की बाकी सदस्य दिन में बाद में पहुंचने वाली थीं। मजूमदार ने कहा कि अलग-अलग खेलों के खिलाड़ियों के साथ रहना, गेम्स

विलेज में समय बिताना और बहु-खेल मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करना खिलाड़ियों के लिए एक अलग अनुभव होगा। उन्होंने कहा, 'बहु-खेल आयोजन का माहौल ऐसी चीज है, जिसका टीम बेसब्री से इंतजार कर रही है। हम चाहते हैं कि खिलाड़ी इस अनुभव का भी आनंद लें।' उन्होंने यह भी बताया कि टीम को आवास को लेकर कोई परेशानी नहीं है। भारतीय टीम हाल के मुकाबलों में शानदार फॉर्म में रही है और इस दौरान श्री चरणी ने गेंदबाजी में अहम भूमिका निभाई है। 22 वर्षीय बाएं हाथ की स्पिनर ने टी20 एशिया कप में 12 विकेट लेकर प्रभावशाली प्रदर्शन किया। श्री चरणी ने लगातार अच्छे प्रदर्शन के दम पर टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में केवल 30 मैचों में 50 विकेट का आंकड़ा भी पार कर लिया है।

संजू-अभिषेक की तूफानी पारी से भारत ने अफगानिस्तान को सात विकेट से हराया, सीरीज पर कब्जा

एजेंसी

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम ने यहां अरुण जेटली स्टेडियम में 24,215 दर्शकों के सामने शानदार प्रदर्शन करते हुए अफगानिस्तान को दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में सात विकेट से हरा दिया। भारत ने 160 रन के लक्ष्य को महज 14.5 ओवर में तीन विकेट खोकर हासिल कर लिया। ईशान किशन ने चौका लगाकर भारत को जीत दिलाई। भारत ने 14.5 ओवर में तीन विकेट पर 163 रन बनाकर जीत दर्ज की। इस जीत के साथ भारत ने तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। दोनों टीमों के बीच तीसरा और आखिरी मुकाबला 17 सितंबर को खेला जाएगा। भारत की जीत के नायक संजू सैमसन रहे, जिन्होंने महज 22 गेंदों पर चार छक्कों और सात चौकों की मदद से 57 रन की तूफानी पारी खेली। उनके अलावा अभिषेक शर्मा ने 19 गेंदों पर चार

छक्कों और दो चौकों की मदद से 39 रन बनाए। ईशान किशन ने 23 गेंदों पर तीन चौकों और दो छक्कों की मदद से नाबाद 38 रन बनाए, जबकि तिलक वर्मा 14 गेंदों पर 15 रन बनाकर नाबाद रहे 160 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने तूफानी शुरुआत दिलाई। दोनों ने शुरुआती छह ओवरों में ही 82 रन जोड़कर अफगानिस्तान को दबाव में डाल दिया। सातवें ओवर की पहली गेंद पर अभिषेक ने राशिद खान की गेंद पर शानदार छक्का लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर वह सेदीकुल्लाह अटल के हाथों कैच हो गए। उन्होंने 19 गेंदों पर 39 रन बनाए। इसके बाद संजू सैमसन ने चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया और अगली गेंद पर शानदार छक्का जड़ा। हालांकि इसी ओवर में राशिद खान की गेंद पर वह मोहम्मद नबी को कैच दे बैठे। संजू ने 22 गेंदों पर 57 रन बनाए। उनका विकेट 99 रन के कुल स्कोर पर गिरा। 11वें ओवर में 123 के कुल स्कोर पर राशिद खान ने भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर को आउट कर भारत को तीसरा झटका दिया। राशिद की गेंद पर इब्राहिम जादरान ने स्लिप में श्रेयस अय्यर का शानदार कैच पकड़ा। अय्यर ने 11 गेंदों पर 11 रन बनाए। इसके बाद ईशान किशन और तिलक वर्मा ने मोर्चा संभाल लिया। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 25 गेंदों पर नाबाद 40 रन की साझेदारी करते हुए भारत को 14.5 ओवर में सात विकेट की आसान जीत दिला दी।

एशियाई खेलः भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीमों को गांधीनगर में दी गई गर्मजोशी से विदाई

एजेंसी

गांधीनगर। जापान के आइची-नागोया में होने वाले 20वें एशियाई खेलों के लिए रवाना होने वाली भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीमों को मंगलवार सुबह भारतीय खेल प्राधिकरण के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र गांधीनगर में गर्मजोशी से विदाई दी गई।

पुरुष टीम की कमान मुख्य कोच बलवान सिंह संभाल रहे हैं, जबकि बीसी रमेश और अनूप कुमार सहायक कोच हैं। महिला टीम की मुख्य कोच नीता दादवे हैं और ममता पूजारी सहायक कोच की भूमिका में हैं। दोनों टीमों में 12-12 खिलाड़ी हैं और उनके साथ कोचिंग तथा सहयोगी स्टाफ भी मौजूद है।

दोनों टीमों ने एशियाई खेलों की तैयारियों के तहत 5 से 14 सितंबर तक साई राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र गांधीनगर में अपना अंतिम प्रशिक्षण शिविर लगाया। विदाई समारोह में खिलाड़ियों को

पारंपरिक तिलक लगाया गया और माला पहनाई गई। दोनों टीमों के कोच, कप्तान और उप-कप्तानों को पारंपरिक शॉल भी भेंट किए गए।

महिला टीम की कप्तान पुष्पा राणा और पुरुष टीम के कप्तान सुनील कुमार ने अपनी-अपनी टीमों की तैयारियों पर भरोसा जताते हुए कहा कि दोनों टीमें आइची-नागोया में 2022 एशियाई खेलों की सफलता दोहराने के लिए तैयार हैं।

पुष्पा राणा ने भारत में बढ़ती लीग संस्कृति को कबड्डी के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा, 'हमारे देश में लीग संस्कृति न केवल हमारी टीम और खिलाड़ियों के विकास में मदद कर रही है बल्कि दूसरे देशों में भी कबड्डी को मजबूत कर रही है। अलग-अलग देशों के खिलाड़ी और कोच हमारी लीग के जरिए अनुभव हासिल कर रहे हैं और उसे अपने देशों में लेकर जा रहे हैं। इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस खेल का स्तर बढ़ रहा है। साई राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र गांधीनगर में कबड्डी के लिए उपलब्ध विशेष सुविधाओं ने भी हमारी तैयारियों के लिए बहुत अच्छा माहौल दिया है।'

चैंपियंस लीग फाइनल की मेजबानी करेगा बार्सिलोना का कैंप नोउ

एजेंसी

बार्सिलोना। यूएफा ने घोषणा की कि बार्सिलोना का पुनर्निर्मित कैंप नोउ 2029 चैंपियंस लीग फाइनल की मेजबानी करेगा। बार्सिलोना के स्टेडियम ने लंदन के वेम्बली स्टेडियम को पीछे छोड़कर मेजबानी हासिल की। 2029 का फाइनल बार्सिलोना के लिए खास होगा क्योंकि इसके एक साल बाद स्पेन पुर्तगाल और मोरक्को के साथ मिलकर 2030 विश्वकप की मेजबानी करेगा। 2030 विश्वकप का फाइनल कहां होगा, इसे लेकर भी मुकाबला जारी है। इसके लिए रियल मैड्रिड के पुनर्निर्मित सैंटियागो बर्नाबेउ और कासाब्लांका में बन रहे 1,15,000 दर्शक क्षमता वाले स्टेडियम के नाम चर्चा में हैं।यूएफा की कार्यकारी समिति ने साल 2028 चैंपियंस लीग फाइनल के लिए म्यूनिख स्थित बायर्न म्यूनिख के स्टेडियम को भी चुना है। इस आयोजन के लिए म्यूनिख एकमात्र दावेदार था। यहां 2025 में भी चैंपियंस लीग फाइनल खेला गया था। करीब 1,05,000 दर्शक क्षमता वाले कैंप नोउ का पुनर्निर्माण अभी जारी है। स्टेडियम के ऊपरी हिस्से और छत का निर्माण अभी पूरा होना बाकी है।बार्सिलोना ने इससे पहले 1999 में चैंपियंस लीग फाइनल की मेजबानी की थी। उस मुकाबले में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इंजरी टाइम में दो गोल कर बायर्न म्यूनिख को चौंकाते हुए खिताब जीता था।

वेम्बली में 1999 के बाद तीन बार चैंपियंस लीग फाइनल खेला जा चुका है। लंदन के इस ऐतिहासिक स्टेडियम ने साल 2011, 2013 और 2024 में फाइनल की मेजबानी की थी। यूरोपीय कप के 71 साल के इतिहास में वेम्बली कुल आठ बार फाइनल की मेजबानी कर चुका है। इस सत्र का चैंपियंस लीग फाइनल मैड्रिड के एटलेटिको मैड्रिड के मेट्रोपोलितानो स्टेडियम में खेला जाएगा। महिला चैंपियंस लीग के 2028 फाइनल की मेजबानी रिकॉर्ड आठ बार की चैंपियन लियोन करेगा। वहीं, 2029 महिला चैंपियंस लीग फाइनल कार्डिफ के राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। यही स्टेडियम 2028 यूरोपीय चैंपियनशिप के उद्घाटन मैच की भी मेजबानी करेगा। यूएफा ने यूरोपा लीग के 2028 और 2029 फाइनल के मेजबान भी तय कर दिए हैं। 2028 का फाइनल रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट के राष्ट्रीय स्टेडियम में और 2029 का फाइनल सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में बनने वाले नए राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा।

एमसीडी ने 296 सफाई कर्मचारियों को किया नियमित, महापौर ने दी बधाई

एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे 296 दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मचारियों को नियमित कर दिया है। महापौर प्रवेश वाही ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए सभी संबंधित कर्मचारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि दिल्ली की स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने में सफाई कर्मचारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये कर्मचारी कठिन परिस्थितियों में भी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ दिल्ली को स्वच्छ रखने में अपना योगदान देते हैं। निगम प्रशासन द्वारा जोनल स्क्रीनिंग कमेटियों की संस्तुतियों तथा संबंधित अधिकारियों की अनुशंसा के आधार पर कुल 296 सफाई कर्मचारियों के नियमितीकरण का निर्णय लिया गया है। इनमें 01 अप्रैल 1998 से 31 मार्च 2000 के बीच सामान्य रूप से कार्यरत 160 दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मचारियों को 01 अप्रैल 2006 से तथा 01 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2002 के बीच कार्यरत 136 दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मचारियों को 01 अप्रैल 2008 से नियमितीकरण का लाभ प्रदान किया गया है। महापौर ने कहा कि यह निर्णय लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे सफाई कर्मचारियों के लिए सम्मान, सुरक्षा और स्थायित्व की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली नगर निगम कर्मचारियों के कल्याण तथा उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए निरंतर कार्य कर रहा है।

दिल्ली सरकार 10,000 छात्रों के लिए बनेगी हॉस्टल

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी को शिक्षा हब बनाने के साथ-साथ दिल्ली सरकार ने 10 हजार छात्रों के लिए हॉस्टल बनाने का फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने 10 हजार छात्रों के लिए सुरक्षित और किफायती हॉस्टल बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने यह हॉस्टल छात्र और छात्राओं दोनों के लिए होंगे। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर विडियो जारी करते कहा कि ये हॉस्टल लड़के और लड़कियों, दोनों तरह के छात्रों के लिए होंगे। दिल्ली के किसी भी विश्वविद्यालय या कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र इन सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने कहा कि हमने हॉस्टल बनाने में सक्षम संबंधित विभागों के साथ बैठकें की हैं, सही जगहें चुनी हैं और एक नीति का ड्राफ्ट तैयार करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने छात्रों की जरूरतों और इन हॉस्टलों में जरूरी सुविधाओं पर अच्छी तरह से विचार किया है। सरकार ऐसे हॉस्टल बनाएंगी, जहां देश भर के माता-पिता अपने बच्चों को पूरी निश्चिंतता के साथ छोड़ सकें, और जहं छात्र–खाने या रहने की चिंता से मुक्त होकर–पूरी तरह से अपने सपनों को पूरा करने पर ध्यान दे सकें। उन्होंने कहा कि हॉस्टलों के लिए जगहों की पहचान की जा रही है और तय समय में इसे लागू करने के लिए एक खास पॉलिसी तैयार की जा रही है।

उप महापौर डॉ. मोनिका पंत ने नेहरू नगर का किया निरीक्षण

नई दिल्ली। दिल्ली को स्वच्छ, सुंदर एवं हरित बनाने की दिशा में चलाए जा रहे प्रयासों के तहत दिल्ली की उप महापौर डॉ. मोनिका पंत ने 'स्वच्छ भारत अभियान' एवं 'दिल्ली को कूड़े से आजादी' अभियान के अंतर्गत दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र के वार्ड संख्या 144 स्थित नेहरू नगर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में सफाई व्यवस्था, पार्कों, गलियों तथा नागरिक सुविधाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उप महापौर ने निगम प्राथमिक विद्यालय, आयुष्मान आरोग्य मंदिर एवं क्षेत्र के पार्कों का भी दौरा किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि क्षेत्र में साफ-सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाए तथा नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, यह सुनिश्चित किया जाए। क्षेत्र की क्षतिग्रस्त गलियों का निरीक्षण करते हुए डॉ. मोनिका पंत ने संबंधित अधिकारियों को टूटी हुई गलियों की मरम्मत का कार्य यथाशीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं से जुड़े कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

16 घंटे में सुलझा हत्या का मामला, मर्डर के आरोप में पति गिरफ्तार

नई दिल्ली। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के आनंद पर्वत थाना पुलिस ने एक महिला की हत्या के मामले में कार्रवाई करते हुए घटना के करीब 16 घंटे के भीतर उसके पति को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, तकनीकी जांच और स्थानीय स्तर पर जुटाई गई खुफिया जानकारी की मदद से आरोपी तक पहुंच बनाई गई। पुलिस के अनुसार, मृतका की उम्र 32 वर्ष थी और वह पंजाबी बस्ती, बलजीत नगर, आनंद पर्वत इलाके में अपने पति, दो बेटियों और मां के साथ रहती थी। 14 सितंबर को आनंद पर्वत थाना पुलिस को एक महिला की संदिग्ध मौत की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे। महिला एक कमरे में मृत अवस्था में मिली। पुलिस के मुताबिक, मृतका की करीब 10 वर्षीय बेटी ने बताया कि तड़के लगभग 3:45 से 4 बजे के बीच उसकी नींद खुली थी। उसने अपने पिता को अपनी मां के पास देखा था। बच्ची के अनुसार, पिता कुछ देर बाद घर से बाहर चले गए। बाद में मां द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं देने की बात सामने आई। शव की शुरुआती जांच में गर्दन के बाईं ओर नाखून जैसे निशान पाए गए।

दिल्ली सरकार ने किशाऊ परियोजना के लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री व जल शक्ति मंत्री का जताया अभार

'प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार वर्षों से लंबित महत्वपूर्ण विषयों का समाधान संवाद और राज्यों की सहमति के माध्यम से कर रही है '

एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना को लेकर हुए महत्वपूर्ण समझौते पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल को धन्यवाद दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार तथा संबंधित राज्यों के सहयोग की सराहना की गई है। उल्लेखनीय है कि आज समझौते के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सरकार की खास प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यमुना के शुद्धिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। यमुना जब स्वच्छ होती है, तो गंगा भी स्वच्छ होती है; क्योंकि

अंततः यमुना प्रयागराज में गंगा में ही समाहित होती है। उन्होंने कहा कि जब तक यमुना की स्वच्छता का स्वप्न पूरा नहीं होता, गंगा की स्वच्छता का स्वप्न भी अधूरा रहेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री और सभी संबंधित लोग पूर्ण सहयोग एवं मनोयोग के साथ यमुना को स्वच्छ बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि किशाऊ परियोजना के समझौते से दिल्ली को 109.9 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) पानी मिल सकेगा, जिससे राजधानी की पेयजल जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। साथ ही यमुना नदी में पर्यावरण के लिए जरूरी जलप्रवाह को बेहतर करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि पानी की कमी दिल्ली की बड़ी चुनौतियों में से एक है। किशाऊ परियोजना के आगे बढ़ने से दिल्ली की जल सुरक्षा मजबूत होगी और कम पानी वाले समय में राजधानी को अतिरिक्त कच्चा पानी उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने कहा कि परियोजना का महत्व केवल दिल्ली को मिलने वाले अतिरिक्त पानी तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे यमुना नदी में पर्यावरण के लिए जरूरी जलप्रवाह को बेहतर करने में भी मदद मिलेगी, जो यमुना के पुनर्जीवन और पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है।

डीयू के एलसी-1 में चुनावी सरगर्मी तेज

सचिव पद पर यशवंत मिश्रा और अरशद आमने-सामने

वहीं सचिव पद के दूसरे प्रत्याशी अरशद भी छात्र एकता और प्रशासनिक जवाबदेही के मुद्दों को लेकर विद्यार्थियों से संपर्क कर रहे हैं।

एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की सरगर्मी बढ़ने के साथ ही लॉ सेंटर-1 (एलसी-1) में भी चुनावी माहौल गरमा गया है। उत्तर परिसर स्थित उमंग भवन और आसपास के क्षेत्रों में प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान तेज हो गया है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव पद के प्रत्याशी छात्रों के बीच पहुंचकर अपनी प्राथमिकताएं और मुद्दे रख रहे हैं। हालांकि, सचिव पद के लिए यशवंत मिश्रा और अरशद के बीच मुकाबला छात्रों के बीच विशेष चर्चा का विषय बना हुआ है। एलसी-1 में अध्यक्ष पद के लिए उमंग पाठक और तुषार कुशवाहा के बीच मुकाबला है, जबकि उपाध्यक्ष पद पर शिवम गौतम और निशांत राणा अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। वहीं सचिव पद पर यशवंत मिश्रा और अरशद आमने-सामने हैं। यशवंत मिश्रा अपने प्रचार अभियान में छात्र हितों से जुड़े बुनियादी और व्यावहारिक मुद्दों को प्रमुखता दे रहे हैं। उनका कहना है कि विधि के विद्यार्थियों के सामने समय की कमी और शैक्षणिक दबाव के साथ-साथ इंटर्नशिप, प्लेसमेंट, पुस्तकालय, पेयजल और अन्य सुविधाओं से जुड़ी चुनौतियां भी हैं। ऐसे में छात्र प्रतिनिधि की भूमिका केवल भाषण देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि परिसर की समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन के साथ लगातार संवाद करना भी जरूरी है। यशवंत मिश्रा के प्रमुख चुनावी मुद्दों में प्लेसमेंट और इंटर्नशिप सेल का पुनर्गठन शामिल है। उनका कहना है कि विधि के विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ अदालतों, कॉरपोरेट लॉ फर्मों और अन्य कानूनी संस्थानों में व्यावहारिक अनुभव की आवश्यकता होती है। उन्होंने सचिव चुने जाने पर पारदर्शी और प्रभावी करियर एवं प्लेसमेंट सेल के गठन की दिशा में काम करने का भरोसा दिलाया है। इसके अलावा एलसी-1 के उमंग भवन में पेयजल की गुणवत्ता का मुद्दा भी उनके एजेंडे में शामिल है। उन्होंने वॉटर कूलरों के पानी की नियमित जांच कराने और आधुनिक आरओ प्रणाली उपलब्ध कराने की बात कही है। परिसर में हाई-स्पीड वाई-फाई सुविधा को मजबूत करना भी उनकी प्राथमिकताओं में है। कैंटीन की व्यवस्था में सुधार को लेकर भी यशवंत मिश्रा ने छात्रों के बीच अपनी बात रखी है। उन्होंने कैंटीन में स्वच्छ भोजन, उचित दर और पर्याप्त बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही है। इसके साथ ही पुस्तकालय के समय में विस्तार, देर रात अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा और मूठ कोर्ट प्रतियोगिताओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने को भी अपने एजेंडे में शामिल किया है।

दिल्ली में इस साल अब तक 179 दिन साफ हवा दर्ज

एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली में 1 जनवरी से 15 सितंबर के बीच 179 साफ हवा के दिन दर्ज किए गए हैं, जो शहर की वायु गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार को दर्शाता है। पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान दिल्ली में 172 स्वच्छ वायु दिवस दर्ज किए गए थे, जबकि 2016 में यह संख्या महज 94 दिन थी। 2016 में 94 दिनों से बढ़कर 2026 में 179 साफ हवा के दिन दर्ज होना 85 दिनों का सुधार दर्शाता है। इस उपलब्धि पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में स्पष्ट और निरंतर सुधार देखने को मिल रहा है। वर्ष 2016 में केवल 94 स्वच्छ वायु दिवसों से बढ़कर इस वर्ष 179 दिन होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह दर्शाता है कि दिल्ली सरकार के निरंतर प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। दिल्लीवासियों को स्वच्छ हवा उपलब्ध कराने के लिए हम इन प्रयासों को और मजबूत करते रहेंगे, ताकि हर मौसम के साथ दिल्ली की हवा और स्वच्छ हो।

उन्होंने कहा कि 15 सितंबर को दिल्ली का एक्यूआई 98 दर्ज किया गया, जो 'संतोषजनक' श्रेणी में

आता है। वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों के विरुद्ध लगातार की जा रही कार्रवाई से वायु गुणवत्ता में सुधार देखने को मिला है।

पर्यावरण विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटों में 81 मैकेनाइज्ड रोड स्वीपर्स द्वारा लगभग 2,279 किलोमीटर सड़कों की सफाई की गई तथा लगभग 170 मीट्रिक टन सड़क की धूल एकत्र कर वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण के लिए भेजी गई। सरकार के प्रयासों में कचरा प्रबंधन और वाहनों से होने वाले प्रदूषण के विरुद्ध कार्रवाई भी शामिल है। पिछले 24 घंटों में लगभग 12,715 मीट्रिक टन कचरा निस्तारित किया गया और वाहनों से होने वाले प्रदूषण से संबंधित उल्लंघनों के लिए 4,976 चालान जारी किए गए। इसी अवधि में लगभग 2,113 मीट्रिक टन एसए×डी (निर्माण एवं मालवा) भी हटाया गया। शहर के एकीकृत कचरा प्रबंधन प्रयासों के तहत भलस्वा, गाजीपुर और ओखला नगर निगम के ठोस कचरा डंपिंग स्थलों पर बायोमाइनिंग के माध्यम से लगभग 19,212 मीट्रिक टन लीगेसी वेस्ट (पुराने संचित कचरे) का प्रसंस्करण किया गया।

आशा कार्यकर्ताओं का मासिक प्रोत्साहन बढ़ाकर किया दोगुना, 6,000 रुपये मिलेंगे

एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में आशा कार्यकर्ताओं के निर्धारित मासिक प्रोत्साहन को दोगुना कर 3,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये करने का निर्णय लिया गया है। यह वृद्धि दिल्ली में सभी कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं पर लागू होगी। अन्य प्रोत्साहन पहले की तरह जारी रहेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आशा कार्यकर्ता दिल्ली की प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। वे घर-घर जाकर लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देती हैं, परिवारों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करती हैं तथा गर्भवती महिलाओं और प्रसूताओं की देखभाल से संबंधित सेवाओं में सहयोग करती हैं।

स्वास्थ्य एवं पोषण दिवसों, स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों, सर्वेक्षणों और सामुदायिक बैठकों में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। कोविड-19 महामारी के दौरान भी आशा कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की थीं। दिल्ली में 6,725 पदों पर आशा कार्यकर्ता कार्यरत हैं। सामान्यतः एक आशा कार्यकर्ता लगभग 2,000 लोगों या 400 परिवारों से जुड़ी होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार आशा वर्करों

का मानदेय बढ़ाने पर लगातार विचार विमर्श कर रही थी। यह निर्णय सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल था, जिसे पूरा कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मासिक प्रोत्साहन में वृद्धि आशा कार्यकर्ताओं के योगदान के सम्मान के साथ-साथ उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे उनके कार्य के प्रति उत्साह और सेवा निरंतरता को बल मिलेगा। साथ ही, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और महिला आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देने में भी सहायता मिलेगी।

अभाविप का तेज हुआ चुनावी अभियान, 1973 से विद्यार्थियों के विश्वास का केंद्र

एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) चुनाव को लेकर विभिन्न महाविद्यालयों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के प्रत्याशी एवं कार्यकर्ता विद्यार्थियों से संवाद कर उनके मुद्दों, अपेक्षाओं और विश्वविद्यालय से जुड़े विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। अध्यक्ष पद के लिए यश डबास, उपाध्यक्ष पद के लिए ईशू मौर्य, सचिव पद के लिए रिया छाबड़ी एवं संयुक्त सचिव पद के लिए लक्ष्यराज सिंह मैदान में हैं। विद्यार्थियों के बीच अभाविप के पैनल को मिल रहे व्यापक समर्थन के साथ 7-3-3-3 मतदान क्रमांक पर अभाविप का पूरा पैनल चुनाव मैदान में हैं। अभाविप दिल्ली के प्रदेश मंत्री सार्थक शर्मा ने कहा कि अभाविप हमेशा से विद्यार्थियों की पहली पसंद रही है। विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए अभाविप ने सदैव जमीन पर काम किया है और विद्यार्थी इससे भली-भांति परिचित हैं। इसके विपरीत जमीन पर अपनी विफलता उजागर कर चुकी एनएसयूआई इस बार भी झूठ और भ्रम का सहारा ले रही है। सार्थक ने कहा कि कांग्रेस-एनएसयूआई में इस वर्ष भी वंशवाद और अवसरवाद साफ दिखाई दे रहा है, प्रमुख कांग्रेस नेता के परिजन को टिकट दिया गया, जबकि असंतुष्ट दावेदार बागी होकर मैदान में उतर गए। जब अपने ही लोगों के बीच समन्वय नहीं है, तो विद्यार्थियों की समस्याओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व कैसे करेंगे? विद्यार्थी यह अंतर समझ चुके हैं और इस बार अभाविप का पूरा पैनल 4-0 की निर्णायक जीत की ओर बढ़ रहा है। परिषद ने बताया कि वर्ष 1954 से डूसू चुनाव आयोजित होते रहे हैं और अभाविप ने 1971 से चुनाव लड़ना शुरू किया। वर्ष 1973 में पहली प्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया में अभाविप ने चारों पदों पर विजय प्राप्त की।

उपराज्यपाल ने की जेजे क्लस्टर पुनर्वास पहलों की समीक्षा

समस्याओं के समाधान का दिया निर्देश

एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने 'दिल्ली स्लम एवं जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026' के तहत बेहतर आवास और रहने की स्थितियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जेजे क्लस्टर पुनर्वास पहलों की समीक्षा की।

उपराज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'सभी के लिए सम्मानजनक आवास' के विजन और गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशों के अनुरूप, यह नीति कट-ऑफ तारीख को एक जनवरी 2025 तक बढ़ाकर कल्याणकारी योजनाओं का दायरा बढ़ाती है। इसमें मौजूदा जगह पर पुनर्विकास, जरूरी नागरिक बुनियादी ढांचे और वैकल्पिक आवास को प्राथमिकता दी गई है।

उपराज्यपाल ने अधिकारियों को निवासियों के संपर्क में रहने, उनकी चिंताओं को सुनने और समस्याओं का तेजी से समाधान करने के निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि निवासियों को जमीनी स्तर पर बदलाव दिखना चाहिए। हर परिवार एक सुरक्षित, सम्मानजनक

घर और बेहतर जीवन-स्तर का हकदार है। विकसित दिल्ली के निर्माण के दौरान कोई भी पात्र परिवार पीछे नहीं छूटना चाहिए। उल्लेखनीय है कि जून में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) की 36वीं बोर्ड बैठक में झुग्गी पुनर्वास को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। बैठक में तय किया गया कि दिल्ली में 1 जनवरी 2025 तक स्थापित सभी पात्र झुग्गी बस्तियों के निवासियों को पुनर्वास का लाभ दिया जाएगा। राजधानी की जेजे बस्तियों में रहने वाले लगभग 4 से 5 लाख परिवारों यानी करीब 20 लाख लोगों के लिए पक्के और सम्मानजनक आवास का मार्ग प्रशस्त हो गया है। लंबे समय से पुरानी पात्रता तिथि के कारण बड़ी संख्या में परिवार पुनर्वास के लाभ से वंचित रह जाते थे। नई कट-ऑफ तिथि तय होने से अब अधिक से अधिक पात्र परिवारों को इसका लाभ मिल सकेगा। इन कॉलोनियों में आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, बच्चों के खेलने के मैदान और अन्य बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। नई नीति में पारिवारिक विस्तार की वास्तविक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जा रहा है।

एमसीडी ने दिल्ली में प्रवर्तन अभियान किया तेज

40 विध्वंस कार्रवाई, 16 संपत्तियां सील

एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने खतरनाक भवनों, अनधिकृत निर्माणों तथा दिल्ली के मास्टर प्लान (एमपीडी) और भवन उपविधियों के उल्लंघन के खिलाफ अपने शहरव्यापी प्रवर्तन अभियान को और तेज कर दिया है। भवन मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने और जनसुरक्षा की रक्षा के लिए निगम के सभी 12 जोनों में सख्त प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली नगर निगम ने गहन प्रवर्तन अभियान के तहत एमसीडी के सभी 12 जोनों में 40 विध्वंस कार्रवाई की गई। इसके अलावा, 16 संपत्तियों को सील किया गया, जबकि लागू भवन मानदंडों और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 4 विध्वंस आदेश पारित किए गए। एमसीडी ने कल भी व्यापक प्रवर्तन अभियान चलाया था, जिसके दौरान दिल्ली के मास्टर प्लान और भवन उपविधियों के उल्लंघन के मामले में 40 संपत्तियों को ध्वस्त किया गया और 8 अन्य संपत्तियों को सील किया गया। लगातार की जा रही यह कार्रवाई अनधिकृत निर्माण पर अंकुश लगाने और वैधानिक प्रावधानों का कड़ाई से

पालन सुनिश्चित करने के लिए निगम के सतत प्रयासों को दर्शाती है।

इस अभियान के दौरान दक्षिण जोन के गौशाला रोड, सतबड़ी तथा पश्चिम जोन के विशाल एन्क्लेव, हस्तसाल, विकासपुरी एक्सटेंशन और उत्तम नगर में प्रमुख विध्वंस कार्रवाई की गई। उत्तरी जोन के सब्जी मंडी क्षेत्र में भी विध्वंस सहित प्रवर्तन कार्रवाई की गई।

पूर्वी जोन में न्यू सीलमपुर, मयूर विहार फेज-I और पांडव नगर में प्रमुख विध्वंस कार्रवाई की गई। एमसीडी के शेष जोनों में भी विभिन्न स्थानों पर इसी प्रकार की प्रवर्तन कार्रवाई की गई।

एमसीडी ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार के अनधिकृत निर्माण या भवन मानदंडों के उल्लंघन की अनुमति नहीं दी जाएगी। एमसीडी ने दोहराया कि जनसुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले उल्लंघनों तथा अपने अधिकार क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण के खिलाफ प्रवर्तन अभियान पूरी सख्ती के साथ जारी रहेगा। निरीक्षण अभियान के तहत एमसीडी ने दिल्लीभर में पेइंग गेस्ट (पीजी) आवासीय भवनों का मैदानी सर्वेक्षण किया है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य संचालित पीजी सुविधाओं का विस्तृत डेटाबेस तैयार करना तथा लागू भवन मानदंडों और नियमों के अनुपालन का आकलन करना है। अब तक किए गए सर्वेक्षण में लगभग 2,453 ऐसे भवनों की पहचान की गई है, जहां पीजी सुविधाएं संचालित हो रही हैं और इनमें करीब 55,000 लोग रह रहे हैं।

पीजी संचालकों के लिए 15 दिन के भीतर तैयार किया जाएगा पोर्टल, नए छात्रावासों के लिए भूमि की करेंगे पहचान

एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली के शिक्षा एवं शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली में पीजी संचालकों के लिए 15 दिनों के भीतर एक पोर्टल तैयार किया जाएगा, जिस पर पीजी सुविधाओं का पंजीकरण किया जाएगा तथा भवन की आयु, संरचना का आकार और अग्नि सुरक्षा संबंधी उपायों का विवरण उपलब्ध कराया जाएगा। यह निर्णय मंत्री आशीष सूद की अध्यक्षता में छात्र आवास एवं सुरक्षा के संबंध में गठित 20 सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति की पहली बैठक लिया गया। उपराज्यपाल द्वारा गठित इस उच्चस्तरीय समिति का उद्देश्य राजधानी में छात्र आवास की गंभीर कमी, सुरक्षा मानकों तथा छात्र आवास के नियमन से जुड़े विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करना और उनका समाधान सुनिश्चित करना है। यह जानकारी एक विज्ञप्ति के जरिए दी गई।मंत्री आशीष सूद की अध्यक्षता वाली यह समिति समग्र नीतिगत दिशा प्रदान करने, विभिन्न विभागों एवं एजेंसियों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने तथा 60 दिनों के भीतर अपनी अंतिम सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगी। समिति में दिल्ली के मुख्य सचिव, दिल्ली पुलिस आयुक्त, एमसीडी आयुक्त, एनडीएमसी अध्यक्ष और डीडीए उपाध्यक्ष–शामिल हैं। इसके अतिरिक्त गृह, राजस्व, स्वास्थ्य, शहरी विकास, विधि, लोक निर्माण विभाग के सचिव तथा मुख्य अग्निशमन अधिकारी भी समिति का हिस्सा हैं। विश्वविद्यालयों की ओर से दिल्ली विश्वविद्यालय, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी तथा दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति इस समिति में शामिल हैं। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव/सचिव समिति के सदस्य सचिव हैं। बैठक में कम उपयोग वाली सरकारी अथवा डीडीए संपत्तियों, जैसे नरेला में खाली सरकारी आवासों, की पहचान कर उन्हें छात्रावासों में परिवर्तित करने की संभावनाओं का पता लगाना तथा सार्वजनिक परिवहन से उनकी कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना है। संस्थागत एवं निजी पीजी आवासों के लिए अनिवार्य पंजीकरण व्यवस्था और केंद्रीय डेटाबेस तैयार करना, लीज एग्रीमेंट को विनियमित करना, मनमाने बिजली अधिभार पर रोक लगाना तथा क्षेत्रवार किराया सीमा निर्धारित करना है।